कमल संदेश
ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक

संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य

सत्यपाल

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल
विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798
Qku (dk-) : +91(11) 23381428
QDI : +91(11) 23387887
पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

ई–मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय–सूची

आवरण कथा

नरेंद्र मोदी बने भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार..... 15

मुद्दा : मुजफ्फरनगर दंगा

भाजपा का राष्ट्रपति को ज्ञापन..... 9

लेख

न्यूक्लियर देयता समझौते पर अमरीकी विक्रेताओं का दबाव
–**अरुण जेटली**..... 13

सावरकर के बारे में डा0 अम्बेडकर का ऐतिहासिक रहस्योद्घाटन
–**लालकृष्ण आडवाणी**..... 19

पूरे भारत में मोदी की महत्वपूर्ण स्थिति
–**तथागत राय**..... 22

सांप्रदायिकता की प्रतिस्पर्धा
–**हृदयनारायण दीक्षित**..... 24

विकास पथिक की झोली में आशीर्वाद की सौगात
–**भरतचंद्र नायक**..... 26

अन्य

भाजपा अध्यक्ष का प्रवास..... 7

हरियाणा : पूर्व सैनिकों की रैली..... 13

छत्तीसगढ़ : पं. दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर संगोष्ठी..... 28

राजस्थान : सुराज संकल्प यात्रा..... 30

मुख पृष्ठ : *नरेंद्र मोदी बने भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार*

कमल संदेश के सभी पाठकों को

नवरात्रि एवं दशहरा

की हार्दिक शुभकामनाएं!

जात-पात के भेदभाव से दूर

दलित जाति में पैदा हुए रविदास परम विरक्त और भगवद्भक्त थे। संतोष और भक्ति को वह सच्चा धन मानते थे। काशी के विख्यात संत स्वामी रामानंद ने उन्हें दीक्षा देते समय आशीर्वाद दिया था, भक्ति के क्षेत्र में तो तुम शिखर पर पहुंचोगे ही, तुम्हारे लिखे पदों से असंख्य लोग प्रेरणा लेकर जीवन सार्थक करेंगे। आगे चलकर रविदास जी ने कई भक्ति पदों की रचना की।

संत रविदास अपने प्रवचन और पदों के माध्यम से सदाचार और नैतिकता की प्रेरणा दिया करते थे। वह कहा करते थे कि भगवान की कृपा उसे प्राप्त होती है, जिसका हृदय लोभ, लालच और अन्य दुर्व्यसनों से मुक्त होकर पवित्र बन जाता है।

एक बार काशी में कुछ संत उनके सत्संग के लिए पहुंचे। किसी ने पूछ लिया, संत की पहचान किस गुण से होती है। क्या संत ऊंची जाति का ही होता है। संत रविदास ने बताया, संतन के मन होत है, सबके हित की बात। घट-घट देखे अलख को, पूछे जात न पात।। यानी सच्चा संत वही है, जो सबके कल्याण की बात सोचता है, जो जात-पात के भेदभाव से दूर रहकर प्राणी मात्र में, सब जगह भगवान के दर्शन करता है।

संत रविदास ने एक जगह लिखा है-

रविदास जन्म के कारनै, होत न कोऊ नीच।

नर को नीच करि डारि है, ओछे करम की कीच।।

यानी, जन्म के कारण कोई ऊंच-नीच नहीं होता। बुरा कर्म ही व्यक्ति को नीच बनाता है।

-शिवकुमार गोयल

(अमर उजाला से साभार)

संपादकीय

दल का नहीं देश का फैसला

देर आयद, दुरुस्त आयद। सबको पता था फैसला यही होना है। सवाल था, कब होना है? होने वाला फैसला हो गया। होना इसलिए था कि इस देश की जनता चाहती थी। जो देश की जनता चाहती है उसके विरुद्ध तो कोई जा नहीं सकता। समय (Time) नामक पत्रिका जिसने भी पढ़ी होगी, वह इस बात से सहमत होंगे कि जो समय का नहीं, समय उसका नहीं। अच्छा हुआ भाजपा ने समय को पहचाना। जनता की नब्ज और नजाकत दोनों का गहरा अध्ययन किया। यहां सवाल उठाया जाता है क्या भाजपा व्यक्ति विशेष की पार्टी हो गयी?

पर हम सभी जानते हैं कि सन् 1995 की घटना, जब मुंबई के आजाद मैदान में आयोजित एक विराट सभा में स्वयं श्री लालकृष्ण आडवाणी ने भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम की घोषणा की थी। देश नेतृत्व के कृतित्व व व्यक्तित्व को जानना चाहता था। श्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व भाजपा है और कृतित्व गुजरात। यह छुपा नहीं है, जगजाहिर है। उन्होंने गुजरात के सपनों को साकार किया और भारत के भविष्य को एक आशा की डोर दी। चेन्नई के टैक्सी ड्राइवर जब यह कहने लगे कि ''हमको, देश को, मोडी चाहिए।'' चेन्नई में भाजपा का गढ़ नहीं है। लेकिन श्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा में रहते हुए उस टैक्सी ड्राइवर के मन में अपना स्थान बनाया है।

देश में भाजपा जहां-जहां नहीं थी वहां अटल जी पहुंच गए थे। व्यक्ति से ही व्यक्ति जुड़ता है और संगठन का विस्तार होता है। आज देश को जैसा प्रधानमंत्री चाहिए वैसा व्यक्तित्व भाजपा में सिर्फ श्री नरेंद्र मोदी नामक शख्सियत का है। किसी भी दल में इस तरह का कोई व्यक्तित्व नहीं है। कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी से श्री नरेंद्र मोदी की तुलना, यह राजनीतिक मजाक है। श्री नरेंद्र मोदी की तुलना आज श्रीमती सोनिया गांधी से भी नहीं की जा सकती। और इसलिए अब तक के आए सभी सर्वे में श्री राहुल गांधी इतने बौने दिखाए गए हैं कि शायद कांग्रेस को स्वत: पुनर्विचार करना चाहिए कि वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री प्रत्याशी होने लायक हैं या नहीं। आम जनता की भावना, सर्वे का आकलन, देश की इच्छा, दल की इच्छा, समर्थकों की इच्छा, सिर्फ-सिर्फ नरेंद्र मोदी! नरेंद्र मोदी!! वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं। वे जीवन में अकेले हैं और अध्ययनशील हैं। देशकाल परिस्थितियों के बारे में विचार करते हैं। चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जहां गुजरात को विकास की ऊंचाइयों पर ले गए वहीं अपनी राजनीतिक सूझबूझ से भारत के अव्वल नेताओं की श्रेणी में प्रथम आ गए।

यही कारण है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह सहित संसदीय बोर्ड के प्रत्येक सदस्य ने मुक्तकंठ से न केवल स्वीकारा, न केवल सराहा बल्कि इस बात पर मुहर लगायी कि हमारे प्रधानमंत्री के अगले उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी होंगे। बार-बार लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लेते हैं और लेना भी चाहिए क्योंकि मूल में श्री नरेंद्र मोदी प्रथमत: स्वयंसेवक है और जो कुछ भी उन्हें सफलता मिली है उसमें संघ के संस्कारों का उल्लेखनीय योगदान है। इससे न वे इनकार कर सकते हैं और न संघ इनकार कर सकता है। संघ अजेय-अमर भारतीय संस्कृति का सबलतम संवाहक है, भारतीयता का उद्घोष है। कृष्ण का पांचजन्य है। राष्ट्र की समिधा है। आहुति और समर्पण उसकी निष्ठा है और ऐसे संस्कारों में पले-बढें, वे इन्हीं सब गुणों के धनी हैं।

भाजपा के उस साहस को भी प्रणाम करना पड़ेगा और श्री राजनाथ सिंह को इस बात के लिए बधाई देनी होगी कि उन्होंने सबको साथ लेकर एक प्रणम्य, विनम्र, जनचेतना संचारित भावनाओं को

आकार और साकार किया। सामान्य व्यक्ति जो बराबरी के कद का हो, ऐसा नहीं कर सकता। जिसके सामने पहले देश-धर्म, फिर दल-धर्म, अंत में स्वयं का धर्म, वही व्यक्तित्व ऐसे फैसले का अग्रदूत बन सकता है। इसलिए श्री राजनाथ सिंह भी दल के सेनापति के नाते इस निर्णय के लिए सर्वाधिक बधाई के पात्र हैं। उनका यह खुलकर कहना कि आज भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए मैं उनसे पहले भाषण करूंगा, यह उनके राजनीतिक एवं हार्दिक उदारता का परिचायक है। समय की मांग है कि राजनीति में उदारता को समझा जाय, महत्व दिया जाय। देश रहेगा तो हम सब रहेंगे। आज देश कंटकाकीर्ण मार्गों से गुजर रहा है। देश में यूपीए की सरकार है लेकिन उसका भारत से कोई सरोकार नहीं रह गया है। भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह कांग्रेस के लिए एक खिलौना बन गये। यही कारण बना कि उन्होंने विदेश से लौटने के बाद कहा कि सन् 2014 में राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और मैं उनके नेतृत्व में भी काम करने को तैयार हूँ। असहाय भाव के ऐसे शब्द भारत के प्रधानमंत्री के नहीं होने चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री लाचार नहीं होना चाहिए। लाचार डॉ. मनमोहन सिंह ने अपनी इस तरह की लाचारी जताकर भारत के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को गहरी ठेस पहुंचाई है।

यही कारण है कि देश को एक संभावनाओं से भरे विकास के गुम्बज की कल्पना चाहिए। वैभवशाली भारत बनाने की कामनाओं के साथ भारत के स्वाभिमान को जगाने और भारत के आत्मविश्वास को मजबूत करने की दिशा में जब कदम उठाने की बात आती है तो सहसा पूरे भारतवासियों के मन में एक ही बात आती है, अब तो देश को श्री नरेंद्र मोदी चाहिए। कांग्रेस जनों की मजबूरी हो सकती है कि जोर से न कहें पर घरेलू चर्चा में उनके मन में भी भाव है कि एक ऐसा व्यक्ति, जिसमें देश अपनी साख को देखता हो, इस समय उसे ही प्रधानमंत्री बनना अनिवार्य होना चाहिए। कांग्रेस चाहे लाख विरोध करे पर उनकी अंतरात्मा में भी भारत पहले है और कांग्रेस बाद में। और जिसके मन में भी भारत पहले होगा वह इस समय यही कहेगा कि श्री नरेंद्र मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री हो। ■

दिल्ली

पहले दिल फिर देश जीतेंगे : राजनाथ सिंह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दिल्ली देश का दिल है और विधानसभा चुनाव में पहले दिल को जीतेंगे और फिर लोकसभा चुनाव में देश को जीतेंगे। वहीं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी श्री नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल होगा, जिसे जीतने के बाद भाजपा फाइनल जीतेगी। दोनों वरिष्ठ नेता 17 सितम्बर को तालकटोरा स्टेडियम में आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के मद्देनजर प्रदेश भाजपा के चुनाव प्रचार अभियान के शंखनाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के विकास का जो मॉडल तैयार किया है, उसे देश में लागू करने का समय आ गया है। दिल्ली में 14 बरस का वनवास पूरा हो चुका है। अब कांग्रेस को सत्ता से हटाने की बारी है। बस कार्यकर्ताओं को एकजुटता बनाए रखनी है। इस मौके पर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वेंकैया नायडू, राज्यसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता श्री रविशंकर प्रसाद, वरिष्ठ नेता श्री बलबीर पुंज, प्रदेश अध्यक्ष श्री विजय कुमार गोयल, दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. हर्षवर्धन व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। नेताओं ने मशाल जलाकर चुनाव अभियान की शुरुआत की। ■

कांग्रेस अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करे : राजनाथ सिंह

मुंबई

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर कांग्रेस में दम है तो 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए अपने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करे।

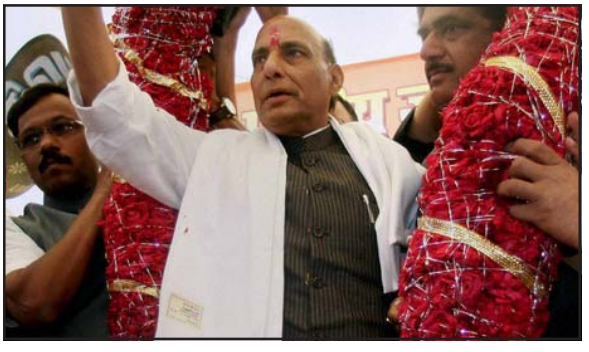

उन्होंने कहा, 'भाजपा ने एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर श्री नरेंद्र मोदी को आगे किया है। मैं कांग्रेस के अपने दोस्तों से जानना चाहूंगा कि क्या वे भी अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। देश जानना चाहता है कि कांग्रेस की तरफ से पीएम पद के लिए उम्मीदवार कौन होगा।' वे 14 सितम्बर को बांद्रा ऑडिटोरियम में एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई नेता कहते हैं कि यूपीए की तरफ से अगले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राहुल गांधी होंगे। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला अवसर होगा कि वर्तमान पीएम अभी सरकार चला रहे हों और अगले चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए सत्तासीन पार्टी किसी और का नाम ले।'

श्री सिंह ने कहा, 'भाजपा ने सर्वसम्मति से एनडीए के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। अब कांग्रेस की बारी है।'

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी में श्री नरेंद्र मोदी को लेकर किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। भाजपा नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी की तारीफ करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वे (आडवाणी) पार्टी के मार्गदर्शक रहे हैं। उनको पार्टी के सदस्यों को अनुशासन में रखने का पूरा अधिकार है। वे कल भी सक्रिय थे, आज भी हैं, और आगे भी सक्रिय रहेंगे।

श्री राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि जनता इस बार बदलाव चाहती है। देश के मिजाज को देखकर लगता है कि भाजपा इस बार के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करेगी। केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह सरकार हर मोर्चे पर असफल रही है।

चंडीगढ़

आईसीयू में पहुंची देश की अर्थव्यवस्था

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया है कि देश आर्थिक, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा तथा कूटनीतिक मोर्चों पर संकट का सामना कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया, 'कांग्रेस नीत संप्रग ने देश की अर्थव्यवस्था को आईसीयू में, भारतीय मुद्रा को वेंटिलेटर पर, डॉलर को एस्कलेटर पर, घरेलू निवेशकों को रनवे पर और हमारे बेरोजगारों को हाईवेपर पहुंचा दिया है। संक्षेप में, इस क्षण हमारे देश के जो हालात हैं उसे ऐसे ही बयान किया जा सकता है। भाजपा अध्यक्ष ने मुजफ्फरनगर दंगों के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर उसने वक्त

रहते प्रभावी कदम उठाए होते तो इस तरह की घटना से बचा जा सकता था।

श्री सिंह ने कहा, 'जब भी सपा सत्ता में आती है, प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा बढ़ी है। अभी तक डेढ़ साल के उनके शासनकाल में 32 जिलों में सांप्रदायिक हिंसा और सांप्रदायिक दंगों की 53 घटनाएं हुई हैं जो इस देश के किसी राज्य के इतिहास में एक रिकार्ड है।'

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पाकिस्तान के साथ बातचीत में कोई 'जल्दबाजी' नहीं दिखानी चाहिए। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से संघर्षविराम का बार-बार उल्लंघन किए जाने पर सरकार को प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। वह आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के पार्टी की बैठक के लिए पहुंचे थे।

लखनऊ

सपा सरकार हर मोर्चे पर विफल

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने प्रदेश की सपा सरकार को मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगों तथा केंद्र सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने प्रदेश

सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया तथा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को भ्रष्टाचार व महंगाई रोकने में पूरी तरह असफल करार दिया।

श्री राजनाथ सिंह 22 सितम्बर को गाजियाबाद में भाजपा कार्यकर्ता संगम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर एक चैनल द्वारा किए गए 'स्टिंग आपरेशन' में सपा नेताओं का असली चेहरा सामने आ गया है। दंगे के लिए सपा के नेता जिम्मेदार हैं लेकिन सपा सरकार भाजपा पर दंगा कराने का आरोप लगाकर अल्पसंख्यकों को गुमराह कर रही है।

सरकार दंगा पीड़ितों को ढाढस तक नहीं बंधा रही बल्कि इस पर भी राजनीति कर रही है। भाजपा कभी लाशों पर राजनीति नहीं करती। भाजपा किसी को डरा कर नहीं बल्कि प्रेम व मोहब्बत से जीतना चाहती है। उन्होंने कहा कि सपा के डेढ़ साल के शासनकाल में 50 से ज्यादा दंगे या तनाव हो चुके हैं। उन्होंने दंगों की निष्पक्ष जांच करने तथा दंगा पीड़ितों की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की।

केंद्र की यूपीए सरकार को उन्होंने कमजोर सरकार बताया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर चुटकी ली कि वे जिसे छू देते हैं वह गायब हो जाती है। कोयला आवंटन से संबंधित फाइलों का गायब होना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि वह इन फाइलों को चोरी मानते हैं और सवाल किया कि आखिर आज तक इसको लेकर रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं की गई? उन्होंने कहा कि आज देश की सीमा असुरक्षित है। पाकिस्तान व चीन केंद्रीय नेतृत्व को कमजोर मान रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2014 के चुनाव में देश की जनता यूपीए सरकार को सत्ता से बेदखल कर भाजपा को सत्ता सौंपेगी। सत्ता में आने के बाद महंगाई पर अंकुश लगाने, रोजगारों का सृजन आदि पर भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में इसके लिए विजन कमेटी बनाई गई है जो सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त कर योजना तैयार करेगी।

उन्होंने कहा कि आजादी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सबसे अच्छी सरकार चली थी। नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि महंगाई पूरी तरह से काबू में थी तथा वर्ष 1998 से 2004 के छह करोड़ 70 लाख लोगों के लिए रोजगार का सृजन हुआ था जबकि यूपीए सरकार के कार्यकाल में केवल 27 लाख लोगों के लिए ही रोजगार का सृजन हुआ।■

'दंगे से निपटने में नाकाम रही सपा सरकार'

सपा सरकार के शासन में कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। उत्तर प्रदेश एक बार फिर सांप्रदायिक दंगे की आग से झुलस रहा है। मुजफ्फरनगर जिला में हुए दंगे में अब तक 49 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग लापता हैं। हजारों की संख्या लोग बेघर हो गए हैं।

'आजतक' टीवी चैनल ने मुजफ्फरनगर दंगा को लेकर स्टिंग ऑपरेशन किया और इसमें यह स्पष्ट हो गया कि सपा सरकार पूरी तरह से दोषी है। यह अपनी तरह की अकेली घटना है, जिस तरह सपा सरकार दंगों में शामिल लोगों को बचाती हुई दिखी। ऑपरेशन में पुलिस अधिकारियों को साफ-साफ सरकार के मंत्री का नाम लेते दिखाया गया। सपा सरकार ने वोटों के लालच में सभी हदों को पार कर दिया है। सपा, बसपा और कांग्रेस सब आपस में अन्दर से मिले हुए हैं और उपर से दिखाने के लिए नूराकुश्ती कर रहे है। दंगा ग्रसित इलाकों का दौरा करने के लिए प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यंक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी को जाने दिया गया। लेकिन भाजपा अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह एवं पार्टी नेता श्री रविशंकर प्रसाद को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने से प्रशासन ने रोक दिया।

गत 20 सितम्बर को दंगा प्रभावित मुजफरनगर जाने से रोके गये भाजपा अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश की सपा सरकार पर आरोप लगाया कि वह उनकी पार्टी के नेताओं को अलग से निशाना बना रही है। सपा को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में जब-जब यह पार्टी सत्ता में आयी है, उसने दंगों को हवा दी है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा, मैं दंगे में मारे गये लोगों के परिजनों से मिलना और हालात का जायजा लेना चाहता था। लेकिन जिला प्रशासन ने यह कह कर मुझे जाने की अनुमति नहीं दी कि वर्तमान स्थिति के चलते ऐसा संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों के हाल के स्टिंग आपरेशन से साबित हो गया है कि हिंसा में उनकी भूमिका है जो आज उत्तर प्रदेश की सत्ता में हैं। उन्होंने कहा, मैंने नहीं जाने का निर्णय किया, लेकिन मैं राज्य सरकार के जिला प्रशासन के रवैये की निंदा करता हूं। मैं वहां लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने जा रहा था, न कि तनाव बढ़ाने। भाजपा अध्यक्ष ने मांग की कि दंगें में जिन परिवारों में जान माल का नुकसान हुआ है उन्हें उचित मुआवजा दिया जाये।

सपा सरकार के खिलाफ भाजपा ने सौंपा राष्ट्रपति को ज्ञापन

मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर भाजपा अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में राज्य के सांसद व विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने 22 सितम्बर 2013 को राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को ज्ञापन सौंपकर अखिलेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग की।

प्रतिष्ठा में
माननीय राष्ट्रपति

महोदय,

हम आपका ध्यान उत्तर प्रदेश की वर्तमान चिंताजनक स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में विगत डेढ़ वर्ष से कानून व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति लगातार बद् से बद्तर होती जा रही है। यह सब उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार के अक्षम प्रशासन एवं साम्प्रदायिक राजनीति से प्रेरित नीतियों के कारण हो रहा है।

विगत कुछ सप्ताहों में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जो कुछ घटनाक्रम हुआ है उसने इस परिस्थिति को भयावह चरम सीमा तक पहुंचा दिया है। एक गांव में घटित हुई मामूली सी छेड़खानी की घटना का अचानक नहीं, बल्कि क्रमशः बढ़ते

हुए इतना बड़ा स्वरूप ले लेना और कई सप्ताह तक लगातार स्थिति बिगड़ते चले जाना, उत्तर प्रदेश सरकार की अक्षमता का और पूर्ण विफलता का प्रमाण है।

भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि मुजफ्फरनगर और आस-पास के क्षेत्रों में हुए साम्प्रदायिक दंगे उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार की साम्प्रदायिक राजनीति से प्रेरित और एक प्रकार से प्रायोजित दंगे है। देश के एक प्रमुख टी0वी0 चैनल द्वारा दिखाये गये स्टिंग ऑपरेशन से यह बात स्पष्ट हो चुकी है किस प्रकार से अपनी साम्प्रदायिक राजनीति से प्रेरित एवं गर्हित उद्देश्यों के लिए किये गये प्रशासनिक हस्तक्षेप ने परिस्थितियों को बिगाड़ने की शुरूआत की और दंगों को विकराल रूप प्रदान करने दिया। इससे हमारे संदेह और आरोप की स्वत: पुष्टि हो रही है।

साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न होने के बाद गिरफ्तारियों से लेकर आम सभाओं तक प्रशासन ने सरकार के दबाव में जिस तरह से एक तरफा कार्यवाहियां कीं, उन्होंने साम्प्रदायिक तनाव को विस्फोटक स्थिति तक पहुंचा दिया। उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च पदस्थ नेताओं की भूमिका साम्प्रदायिक तनाव को बढ़ाने वाली, पक्षपाती एवं संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार के दुरूपयोग की थी। साम्प्रदायिक दंगों को नियंत्रण करने में विफल रहने के बाद कभी समाजवादी पार्टी ने इसे जातीय संघर्ष कह कर साम्प्रदायिक तनाव के साथ-साथ जातीय उन्माद पैदा करने की कोशिश की तो कभी भाजपा पर आधारहीन एवं अनर्गल आरोप लगाकार इस संवेदनशील दु:खद परिस्थिति में राजनीति करने का प्रयास किया।

इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने परिस्थिति को सामान्य करने का प्रयास करने की बजाय अपने पक्ष में साम्प्रदायिक धुव्रीकरण करवाने के राजनैतिक उद्देश्य से भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और अनेक नवयुवकों एवं आम आदमियों पर तथ्यहीन आधारों पर मुकद्मे दर्ज किये। इसमें भाजपा के विधायक श्री सुरेश राणा, श्री संगीत सोम एवं विधानसभा में भाजपा के नेता विधान मण्डल दल श्री हुकुम सिंह भी शामिल हैं। प्रदेश सरकार द्वारा अपनी साम्प्रदायिक राजनीति की पूर्ति के लिए की इस कार्यवाही ने पूरे प्रदेश में साम्प्रदायिक विभेद की खाई को और चौड़ा कर दिया।

श्रीमान्, यह दु:खद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में विगत् डेढ़ वर्षो से लगातार हो रही साम्प्रदायिक दंगों की श्रृखंला के प्रति मूक दर्शक बनी केन्द्र की UPA सरकार ने मुजफ्फरनगर में इन घटनाओं से साम्प्रदायिक तनाव एवं और संवैधानिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते हुऐ देखकर भी कोई कार्यवाही नहीं की। केन्द्र सरकार ने कोई कार्यवाही तो दूर अपितु संविधान द्वारा प्रदत्त अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए कोई चेतावनी या अपनी अप्रसन्नता भी जाहिर नहीं की।

संभवत: संसद में UPA सरकार को सपा के समर्थन के राजनैतिक कारण से केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश ने अपने संवैधानिक दायित्व की बलि चढ़ा रही है और उत्तर प्रदेश की आम जनता को इस भयावह परिस्थिति में अपने हाल पर छोड़ दिया है।

यदि पूरी परिस्थिति को देखें तो आज उत्तर प्रदेश की सपा सरकार में प्रशासनिक मशीनरी फेल हो चुकी है। दंगों में सरकार का राजनैतिक हस्तक्षेप प्रमाणित हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार निष्पक्षतापूर्वक शासन करने के अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करने में विफल हो चुकी है। एक पक्षीय साम्प्रदायिक कार्यवाहियों से जनमानस में सरकार का नैतिक आधार भी ध्वस्त हो चुका है। अत: उत्तर प्रदेश में संवैधानिक व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। केन्द्र की कांग्रेस नेतृत्व की UPA सरकार के साथ सपा का राजनैतिक गठबन्धन उत्तर प्रदेश के लिए एक राजनैतिक दुरभिसन्धि बन चुका है।

अत: हम आपसे भारत की संवैधानिक व्यवस्था के संरक्षक के रूप में निम्न मांग करते हैं।

1. उत्तर प्रदेश में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए तत्काल उ0प्र0 सरकार को बर्खास्त करके, राष्ट्रपति शासन लगाया जाय।
2. इस पूरे घटनाक्रम की उच्चतस्तीय जांच सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीमकोर्ट) के द्वारा नियुक्त न्यायाधीश द्वारा की जाय।
3. दंगों में मारे गये और घायल लोगों को निष्पक्ष रूप से उपयुक्त मुआवजा दिया जाय और तत्काल सम्बन्धित व्यक्तियों को मुआवजे की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाय।
4. दंगों में अनेक निर्दोष आम लोगों पर जो एक तरफा ढंग से उत्पीड़न की कार्यवाही हो रही है वह तत्काल बन्द की जाये।
5. भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर आधारहीन मुकद्दमे वापस लिये जाये।
6. सरकार के जिन नेताओं की संलिप्तता एक स्टिंग ऑपरेशन में स्पष्ट रूप परिलक्षित हो रही है उनके विरूद्ध मुकद्मे कायम किये जाये। ■

रेवाड़ी (हरियाणा) : पूर्व सैनिकों की रैली

'विश्व एक परिवार और भारत सुपर पॉवर बने'

रेवाड़ी (हरियाणा) की एक विशाल रैली में भाजपा के प्रधानमंत्री उम्मीदवार तथा गुजरात के मुख्यमंत्री ने एक सुरक्षित भारत के अपने सपने को साकार करने के लिए अपनी गुंजाएमान आवाज में सम्बोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है और हम भारत के नागरिकों के लिए अपने देश को सुरक्षा, संरक्षण और विश्व शांति के पथ पर अग्रसर करने के लिए बेहद आवश्यक है।

दृढ़ इच्छाशक्ति से ही एक सुरक्षित राष्ट्र और उत्कृष्ट सेना का निर्माण हो सकेगा।

मुझे भारत के सर्वोत्कृष्ट रणनीतिकार आचार्य चाणक्य के जीवन की एक प्रेरणादायक कथा का स्मरण हो आता है। एक अवसर पर जब वह एक पथ पर चल रहे थे तो मार्ग में बिछे कांटों को हटाने के लिए उन्होंने उस पथ पर शहद डालना शुरू कर दिया। उन्हें ऐसा करते हुए देखकर राह में चलते लोग रूक गए और पूछा कि वह उस पथ पर शहद क्यों बिखेर रहे हैं?

इस पर चाणक्य ने जवाब दिया कि जड़ों में शहद डालने से चींटियां वहां घुसने के लिए प्रेरित होंगी और इन जड़ों को नष्ट कर देंगी। चाणक्य ने यह भी कहा कि कांटों को समाप्त करने के लिए उन्हें नष्ट करना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि उनकी जड़ों को भी खत्म करना आवश्यक होता है। इससे हमें यही सबक मिलता है कि हमें सदैव ही समस्या की जड़ को ही समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए।

श्री मोदी की दृष्टि में भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपना आवश्यक है और कहा कि सीमाओं पर घुसपैठ और हमारे जवानों की मृत्यु का कारण उन सीमाओं पर नहीं है, बल्कि जिस तरह से हमारे देश का शासन किया जा रहा है, निहित समस्या उस जगह पर है। उन्होंने लोगों से सीमा सम्बन्धी सभी मुद्दों के विवादों का समाधान दृढ़ इच्छाशक्ति से करने के लिए कहा ताकि एक चुस्त दुरूस्त सेना का निर्माण करते हुए भारत को एक सुरक्षित भारत बनाया जा सके।

सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए युवाओं को मिले प्रेरणा

केन्द्र सरकार पर हमला बोलते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री

ने स्पष्ट रूप से कहा कि आज भारतीय सशस्त्र बल में युवाओं को शामिल करने के लिए न तो पर्याप्त जागरूकता है और न ही कोई प्रेरणा। उनका मत था कि केन्द्र सरकार को यह जागरूकता पैदा करने के लिए सभी उपाय करने चाहिए ताकि युवा सेना में शामिल हों। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे प्रयासों में जरा भी कमी नहीं रहनी चाहिए ताकि हमारे देश को न केवल सेना में भर्ती होने के लिए सभी प्रकार की आवश्यक जानकारियां मिलें, बल्कि उनमें सेना में शामिल होकर राष्ट्र की सेवा करने का अहसास भी पैदा हो सके।

आज भारतीय सशस्त्र बल में युवाओं को शामिल करने के लिए न तो पर्याप्त जागरूकता है और न ही कोई प्रेरणा। उनका मत था कि केन्द्र सरकार को यह जागरूकता पैदा करने के लिए सभी उपाय करने चाहिए ताकि युवा सेना में शामिल हों। हमारे प्रयासों में जरा भी कमी नहीं रहनी चाहिए ताकि हमारे देश को न केवल सेना में भर्ती होने के लिए सभी प्रकार की आवश्यक जानकारियां मिलें, बल्कि उनमें सेना में शामिल होकर राष्ट्र की सेवा करने का अहसास भी पैदा हो सके।

भूतपूर्व-सैनिकों का सम्मान

भाजपा के प्रधानमंत्री उम्मीदवार और गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी ने अनेक घटनाओं और गाथाओं का वर्णन करते हुए हुए भूतपूर्व सैनिकों की सेवाओं के कुशल उपयोग की गहन सराहना की।

इसका एक ज्वलंत उदाहरण है, जिसकी मीडिया में बहुत कम चर्चा हुई है और वह है कि किस प्रकार से गुजरात सरकार ने राज्य में बिजली चोरी करने से रोकने के लिए इन भूतपूर्व सैनिकों का उपयोग किया। इस समस्या का हल निकालने के लिए राज्य सरकार ने 1000 भूतपूर्व सैनिकों को बिजली चोरी रोकने के काम पर लगा कर बिजली चोरी को रोका।

उन्होंने अपनी बात का विस्तार से वर्णन करते हुए कहा कि भूतपूर्व सैनिकों को भारत के हर कस्बे में तैनात किया जा सकता है और उन्हें उन कस्बों में रहने वाले लोगों की सेवा करने के लिए अग्नि-शमन केन्द्रों पर लगाया जा सकता है। यह एक ऐसी सेवा है जिससे राष्ट्र को उनकी मूल्यवान सेवाएं मिल सकती है।

आत्म-निर्भर सुपर पॉवर

इंडिया टूडे कंक्लेव 2013 में, हमने पहली बार नरेन्द्र मोदी से सुना था कि भारत के लिए रक्षा उपकरणों का निर्माण करना अत्यावश्यक है। उन्होंने इसी बात को रेवाड़ी की रैली में फिर दोहराते हुए कहा कि मजबूत रक्षा उपकरणों के निर्माण में पर्याप्त युवा संभावनाओं का पता लगाया जा सकता है जिससे स्वत: ही विश्व में इन उपकरणों की मांग पैदा की जा सकती है। इससे भारत अपने आप ही आत्म-निर्भर सुपर पॉवर बनकर सामने आ जाएगा।

विश्व-एक परिवार

रेवाड़ी रैली में नरेन्द्र मोदी के भाषण में यह कथन सर्वाधिक अद्‌भुत पक्ष को प्रस्तुत कर रहा था। उन्होंने कहा कि भारत का एक सिद्धांत रहा है कि उसने कभी भी अपनी ओर से किसी अन्य देश पर आक्रमण कर विजय प्राप्त करने की कोशिश नहीं की है। हमारे राष्ट्र का सदैव एक प्रेरणा बनी रही है कि पूरा विश्व एक परिवार है, जिसे हम स्वयं अपने देश में और अन्य देशों के साथ भी मान कर चलते हैं। श्री मोदी ने इसे प्रतिपादित करते हुए अपने पड़ोसी देशों- पाकिस्तान और चीन का आह्वान करते हुए कहा कि वे हिंसा का मार्ग छोड़कर एक परिवार के रूप में खड़े हों ताकि हम गरीबी और निरक्षरता जैसी बुराईयों के साथ लड़ सकें। जो कुछ भी श्री मोदी ने कहा, वह महात्मा गांधी के शब्द थे- 'अहिंसा परमो धर्म:', जिसका अर्थ होता है कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। सचमुच धर्म वही है जो किसी मानव या प्राणी को सर्वश्रेष्ठ बनाए, और इस दृष्टांत में अहिंसा वह सिद्धांत है जिस पर भारत मूल रूप से खड़ा है तथा जिसके लिए भारत सर्व विख्यात भी है। इस रैली में पूर्व भारतीय सेनाध्यक्ष ज. वी. के. सिंह की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। ■

भारत का एक सिद्धांत रहा है कि उसने कभी भी अपनी ओर से किसी अन्य देश पर आक्रमण कर विजय प्राप्त करने की कोशिश नहीं की है। हमारे राष्ट्र का सदैव एक प्रेरणा बनी रही है कि पूरा विश्व एक परिवार है, जिसे हम स्वयं अपने देश में और अन्य देशों के साथ भी मान कर चलते हैं। श्री मोदी ने इसे प्रतिपादित करते हुए अपने पड़ोसी देशों- पाकिस्तान और चीन का आह्वान करते हुए कहा कि वे हिंसा का मार्ग छोड़कर एक परिवार के रूप में खड़े हों ताकि हम गरीबी और निरक्षरता जैसी बुराईयों के साथ लड़ सकें।

(सुदर्शन रायबद्रन की रिपोर्ट)

न्यूक्लियर देयता समझौते पर अमरीकी विक्रेताओं का दबाव

✍ अरुण जेटली

गत 3 सितम्बर, 2013 के 'दि हिन्दू' समाचार-पत्र में इस सम्बन्ध में एक खबर प्रकाशित हुई है कि भारत सरकार न्यूक्लियर पॉवर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया (एनपीसीआईपीएल) को अमेरीकी न्यूक्लियर विक्रेताओं को एक लिखित अनुबंध करने की अनुमति देने की योजना बना रही है जिसमें एनपीसीआईएल और अमरीकी विक्रेताओं के बीच इस अनुबंध में एक खण्ड इस सम्बन्ध में होगा कि आप्रेटर एनपीसीआइएल ने 'civil liability for nuclear Damage Act' की धारा 17 में दिए प्रावधान के अनुसार 'वसूली के अधिकार' (Right of recourse) का परित्याग कर दे और इसे स्वेच्छापूर्वक छोड़ दे। इस खबर में बताया गया है कि यह दृष्टिकोण भारत के अटार्नी जनरल की इस सम्मति पर आधारित है कि इस अधिनियम की धारा 17 में यह स्पष्ट रूप से एक लिखित अनुबंध का प्रावधान है और इस अनुबंध में 'वसूली के अधिकार' को बाहर रखने का चुनाव स्वयं आप्रेटर को ही करना है।

न्यूक्लियर विक्रेताओं के दबाव में भारत सरकार 'वसूली के अधिकार' को समाप्त करना चाहती है। लोकसभा में पेश किए गए मूल बिल में धारा 17 में एक प्रावधान है जिसमें घोर उपेक्षा के किसी कार्य से उत्पन्न 'वसूली का अधिकार' बाध्यकारी होगा। मूल रूप से लिखी गई धारा 17 (बी) के प्रारूप में वसूली के अधिकार के प्रयोग के लिए यह पहली शर्त थी कि आपूर्तिकर्ता ने कोई कृत्य जानबूझ कर न किया गया है, जिससे हानि होती है। इस प्रावधान को स्थायी समिति के पास भेजा गया था। भारत सरकार ने विपक्षी दलों से, और विशेष रूप से प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के साथ बातचीत की। भाजपा ने भारत सरकार को कई सुझाव दिए थे। मैं इन चर्चाओं में भागीदार था।

धारा 17 (बी) को फिर से लिखा गया और एक आम सहमति की भाषा की तैयार की गई जिसमें कई दायित्व के सिद्धांत को रखा गया। यदि यह साबित होता है कि आपूर्तिकर्ता का उपकरण जाहिर तौर पर या प्रच्छन्न रूप से, त्रुटिपूर्ण है या उसकी सेवाएं निकृष्ट प्रकार की है तो ऐसी स्थिति में आपूर्तिकर्ता के किसी कार्य का जानबूझकर या उसकी घोर उपेक्षा को कृत्य मानना आवश्यक नहीं होगा अर्थात् उससे वसूली की जा सकेगी। भारत सरकार को दिए गए विभिन्न वैकल्पिक सुझावों के बीच इस परिवर्तित भाषा ने विक्रेताओं को बड़ा असहज कर दिया। हालांकि बिल के धारा 17(ए) और 17(बी) एक-दूसरे से स्वतंत्र थे- एक का प्रभाव दूसरे पर निर्भर नहीं था- फिर भी इस विषय पर बिना किसी चर्चा के शब्द 'और' को स्थायी समिति की रिपोर्ट में डाल दिया गया। इस प्रकार का प्रयास एक फूहड़पन का द्योतक था जिसमें स्थायी समिति द्वारा सदस्यों में परिचालित मूल रिपोर्ट में शब्द 'और' नहीं था। इसे बाद में सोचकर एक 'स्टेप्लड' पृष्ठ में जोड़ा गया और इस प्रकार स्थायी समिति की सिफारिशों वाले मूल पृष्ठ के स्थान पर लगाया गया। मैंने इस आधार पर इसका कड़ा विरोध किया था कि धारा 17 (ए) और 17(बी) एक दूसरे से अलग है। आप्रेटर वसूली के अधिकार के प्रयास को किसी लिखित अनुबंध में ऐसी स्थिति में निर्भर नहीं बनाया जा सकता है यदि यह पता चले कि उसके

न्यूक्लियर विक्रेताओं के दबाव में भारत सरकार 'वसूली के अधिकार' को समाप्त करना चाहती है। लोकसभा में पेश किए गए मूल बिल में धारा 17 में एक प्रावधान है जिसमें घोर उपेक्षा के किसी कार्य से उत्पन्न 'वसूली का अधिकार' बाध्यकारी होगा। मूल रूप से लिखी गई धारा 17 (बी) के प्रारूप में वसूली के अधिकार के प्रयोग के लिए यह पहली शर्त थी कि आपूर्तिकर्ता ने कोई कृत्य जानबूझ कर न किया गया है, जिससे हानि होती है। इस प्रावधान को स्थायी समिति के पास भेजा गया था। भारत सरकार ने विपक्षी दलों से, और विशेष रूप से प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के साथ बातचीत की। भाजपा ने भारत सरकार को कई सुझाव दिए थे।

उपकरण जाहिर तौर पर या प्रच्छन्न रूप से त्रुटिपूर्ण हैं। यदि किसी लिखित अनुबंध में वसूली के अधिकार को इस बात पर निर्भर बना दिया जाता है, जिसके कारण वसूली का अधिकार छिन जाता है, तो इससे यह अधिकार ही पूर्णतः समाप्त हो जाता है।

इस मुद्‌दे पर यूपीए सरकार की झांसेबाजी शर्मनाक है। न्यूक्लियर विक्रेताओं के यहां छिपा हाथ का दबाव अब तक बना हुआ है। धारा 17(बी) का भाषा को फिर से बदल दिया गया और धारा 17(बी) में प्रावधान में शब्द 'आशय' (Intent!) को डाल दिया गया जिससे कड़ी 'देयता' का सिद्धांत ही समाप्त हो गया और सप्लायर द्वारा उपकरण के त्रुटिपूर्ण होने पर उसके साथ आशयपूर्ण शर्त जोड़ दी गई। मैंने इस पर फिर अपना विरोध प्रगट किया और इसे समाप्त कराया। 17(बी) को जो लिखित अनुबंध में धारा 17 (ए) से स्वतंत्र रूप से संचालित होती है, संसद के दोनों सदनों में पारित कर दिया था। राज्यसभा में मेरे भाषण और मंत्री महोदय के उत्तर में पर्याप्त रूप से इस विभेद को स्पष्ट किया गया है।

परन्तु, आखिर कोई भी चीता अपने दाग नहीं धो सकता है। सरकार की वसूली के अधिकार की मंशा कम करने की थी और इसे अनुबंध में निर्भरता प्रदान करने की मंशा जारी रही। जब अधिनियम की नियमावली को अधिसूचित किया गया, ऐसी मंशा स्पष्ट रूप से नियम 24 में प्रगट हुई। नियम 24 का सरोकार अधिनिमय की धारा 17(ए) से है और इसमें प्रारम्भिक लाइसेंस की अवधि निर्दिष्ट करने की अनुमति दी गई है। 'उत्पाद की देयता अवधि' की परिभाषा में वह अवधि रखी गई है जिसमें सप्लायर ने जाहिर तौर पर या प्रच्छन्न रूप से उस उत्पाद के त्रुटिपूर्ण होने की जिम्मेदारी ली है। हांलाकि नियम 24 का सरोकार अधिनियम की धारा 17(ए) से है, फिर भी अधिनियम की धारा 17(बी) को ज्यों का त्यों उठाकर उत्पाद देयता की अवधि की परिभाषा में रख दिया गया है, जिससे खण्ड 17(ए) और 17(बी) को एक-दूसरे के साथ मिला कर पढ़ने, न कि पृथक रूप से पढ़ने के कारण अस्पष्टता पैदा हो गई है। तथ्य यह है कि धारा 17(ए) (बी) और (सी) एक-दूसरे से स्वतंत्र है- यह बात धारा 17(सी) की भाषा से स्पष्ट है जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि के कारण होने वाली न्यूक्लियर क्षति से वसूली का अधिकार प्राप्त है। स्पष्ट है कि इस प्रकार का व्यक्ति न्यूक्लियर सप्लायर से अलग व्यक्ति होगा।

~~~~~~~~~~☯☯☯~~~~~~~~~~

यदि अब एनपीसीआईएल आप्रेटर- सरकारी कम्पनी को दिए गए इस अधिकार का परित्याग करती है तो वह राज्य के राजस्व के साथ समझौता ही करेगी। यह अधिनियम की धारा 17(बी) के प्रावधानों के विरूद्ध होगा। यदि कोई सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम जानबूझकर किसी विदेशी विक्रेता के साथ अनुबंध करता है और अपनी वसूली के अधिकार का परित्याग करता है, जो कि धारा 17बी अन्यथा उस कम्पनी के लाभ के लिए है तो वह न केवल civil liability for Nuclear Damages Act ***के प्रावधानों का अतिक्रमण करेगा, बल्कि इससे भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम की धारा 13(1) (5) का भी उल्लंघन होगा जिससे सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी के राजस्व की हानि होगी।***

~~~~~~~~~~☯☯☯~~~~~~~~~~

जब बिल का प्रारूप बना और पुनः प्रारूप बना तो मैं सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत में शामिल रहा हूं और मैंने संसद की बहस में भाग लिया है, जिस समय इस बिल को विधायी रूप दिया गया था, इसलिए मुझमें इस बात का जरा भी संदेह नहीं है कि अधिनियम की धारा 17(बी) के लिए अधिनियम की धारा 17(ए) के अधीन लिखित अनुबंध कोई पूर्व शर्त नहीं है।

दोनों प्रावधान एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप में काम करते हैं। अधिनियम की धारा 17(बी) को कम करने के स्तर पर प्रारूप तैयार करने में सरकार के बार-बार किए गए प्रयास विफल रहे। समसामयिक काल में मीडिया की रिपोर्टें इसकी साक्षी हैं। यदि अब एनपीसीआईएल आप्रेटर- सरकारी कम्पनी को दिए गए इस अधिकार का परित्याग करती है तो वह राज्य के राजस्व के साथ समझौता ही करेगी। यह अधिनियम की धारा 17(बी) के प्रावधानों के विरूद्ध होगा। यदि कोई सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम जानबूझकर किसी विदेशी विक्रेता के साथ अनुबंध करता है और अपनी वसूली के अधिकार का परित्याग करता है, जो कि धारा 17बी अन्यथा उस कम्पनी के लाभ के लिए है तो वह न केवल civil liability for Nuclear Damages Act के प्रावधानों का अतिक्रमण करेगा, बल्कि इससे भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम की धारा 13(1) (5) का भी उल्लंघन होगा जिससे सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी के राजस्व की हानि होगी। ■

(लेखक राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं)

नरेंद्र मोदी बने भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार
चहुंओर मना जश्न

भाजपा चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष व गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करेंगे। भाजपा ने श्री मोदी को 13 सितम्बर 2013 को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया। संसदीय बोर्ड के फैसले की जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में दी।

भाजपा द्वारा गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर देश भर में जमकर जश्न मनाया गया। नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाये और पटाखे छोड़े। कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे का मुंह मीठा करा बधाई दी।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पार्टी की परम्परा है कि जब भी लोकसभा चुनाव होते हैं उससे कुछ समय पहले चुनावों में नेतृत्व करने वाले नेता का नाम घोषित किया जाता है। इस बार पार्टी ने जन भावना को ध्यान में रखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अगले लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हम संसदीय बोर्ड की ओर से मोदी को बधाई देते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि अगले चुनावों में जनता का समर्थन हमें मिलेगा और केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी जी को आडवाणी जी का समर्थन है। उन्होंने बताया कि राजग सहयोगियों ने श्री मोदी के नाम पर अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके बाद संसदीय बोर्ड के सदस्यों और पार्टी पदाधिकारियों ने श्री मोदी का स्वागत और सम्मान किया। इसी कड़ी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज और पूर्व भाजपा अध्यक्ष डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने उन्हें बधाई दी तो श्री मोदी ने दोनों नेताओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया।

इस अवसर पर श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अनेक वर्षों तक एक कार्यकर्ता के रूप में भिन्न-भिन्न दायित्व निभाते

भारतीय जनता पार्टी
BHARATIYA JANATA PARTY

भारतीय जनता पार्टी
BHARATIYA JANA A PARTY

भारतीय जनता पार्टी
BHARATIYA JANATA PARTY

A PARTY

JANATA PA TY

तीय जनता पार्टी
RATIYA JANATA PARTY

हुए परमात्मा ने जितनी शक्ति और समझ दी है उसका उपयोग भाजपा के विस्तार और विकास के लिए, देश की सेवा करने के लिए करता रहा हूं और हमारी पार्टी ने सदैव मुझे अवसर दिया है। आज पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझ जैसे एक सामान्य परिवार और छोटे से कस्बे से आये एक कार्यकर्ता को बहुत बड़े कार्य का दायित्व दिया है। उन्होंने कहा कि अटल जी, आडवाणी जी के अथाह परिश्रम से खड़ी इस पार्टी के कार्यकर्ताओं की शुभकामनाएं और राष्ट्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद हमें सफलता दिलाएंगे। ''मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को विश्वास दिलाता हूं कि 2014 के चुनावों में भाजपा विजयी हो उसके लिए परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। सामान्य आदमी और कार्यकर्ताओं की आकांक्षाओं पर खरा उतरूं इसके लिए प्रयास करूंगा।'' उन्होंने

कहा कि मैं जनता से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आज जब देश संकट की घड़ी से गुजर रहा है ऐसे में भाजपा को समर्थन देकर देश को संकट से निकालें। उन्होंने समर्थन के लिए राजग सहयोगियों और मीडिया का भी आभार जताया।

अटलजी, आडवाणीजी के घर जाकर लिया आशीर्वाद

भाजपा संसदीय दल के निर्णय के बाद श्री नरेंद्र मोदी शाम में एनडीए के अध्यक्ष व पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी से मिलने नेताद्वय के नई दिल्ली स्थित निवास पर गए और उनका आशीर्वाद लिया।

भाजपा नेता बोले...

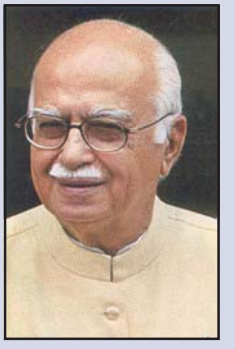

श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भाजपा सही दिशा की ओर बढ़ रही है और निश्चित ही 2014 के आम चुनावों में उसे ऐतिहासिक विजय प्राप्त होगी।

-लालकृष्ण आडवाणी,
अध्यक्ष, भाजपा संसदीय दल

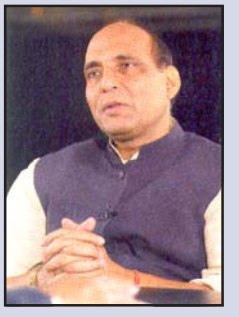

लोगों की भावनाओं व अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। निर्णय से पहले सभी सहयोगियों की सहमति भी ली गई है।

-राजनाथ सिंह
राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा

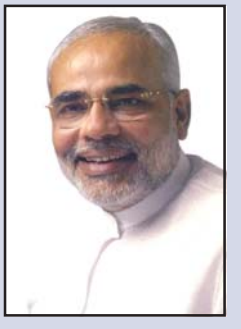

मुझे भरोसा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देश कमल को अपनाएगा। लोस चुनाव में भाजपा की जीत के लिए जान लड़ा दूंगा।

- नरेन्द्र मोदी,
भाजपा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार

जनहित का ध्यान रखते हुए अगले आम चुनावों के लिए यह निर्णय किया गया है। स्पष्ट है कि इसे देखते हुए श्री मोदी ने अपनी बढ़ती लोकप्रियता में शेष सभी को कोसों पीछे छोड़ दिया है।

-अरुण जेटली,
राज्यसभा में विपक्ष के नेता

सावरकर के बारे में डा0 अम्बेडकर का ऐतिहासिक रहस्योद्घाटन

लालकृष्ण आडवाणी

फरवरी, 2003 में पहली बार संसद के सेंट्रल हॉल में स्वातंत्र्य वीर सावरकर का चित्र लगाया गया। उस समय एनडीए सरकार थी श्री वाजपेयी प्रधानमंत्री और श्री मनोहर जोशी लोक सभा के अध्यक्ष। राष्ट्रपति डा0 अब्दुल कलाम ने तैलचित्र का अनावरण किया।

संसदीय इतिहास में, पहली बार कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति के कार्यक्रम का बहिष्कार किया। तबसे प्रत्येक 28 मई को वीर सावरकर की जन्मतिथि पर जब सांसद सेंट्रल हॉल में इस महान स्वतंत्रता सेनानी को अपनी श्रद्धांजलि देने आते हैं तो कांग्रेसी सांसद इस कार्यक्रम का बहिष्कार करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी अपने इस व्यवहार पर सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण नहीं दिया है। परन्तु अघोषित कारण यह है कि वह गांधी हत्या केस में एक आरोपी थे। पार्टी इस तथ्य की अनदेखी करती है कि न्यायालय ने इस केस में दो को मृत्युदण्ड और अन्यों को विभिन्न कारावासों की सजा दी थी परन्तु वीर सावरकर को "दोषी नहीं पाया'' और उन्हें बरी किया।

महात्मा गांधी की हत्या के दो दशक बाद, साहित्यिक और गैर-साहित्यिक पुस्तकों के एक प्रसिद्ध लेखक मनोहर मालगांवकर ने भारतीय इतिहास की इस दु:खद त्रासदी पर आधारित एक पुस्तक लिखी। सजा काटकर बाहर निकले आरोपियों तथा सरकारी गवाह बने बडगे जिसे माफी दे दी गई से पुस्तक लेखक के साक्षात्कारों पर आधारित है।

लेकिन इस पुस्तक के प्रकाशित होने से काफी पहले ही मालगांवकर ने यह रिपोर्ट उस समय की सर्वाधिक प्रतिष्ठित पत्रिका 'लाइफ इंटरनेशनल' को दे दी। इस पत्रिका ने फरवरी, 1968 के अपने अंक में मालगांवकर द्वारा दिए गए तथ्यों को उपरोक्त वर्णित व्यक्तियों के घरों पर खींचे गए फोटोग्राफ के साथ प्रकाशित किया।

गांधीजी की हत्या जिसने दुनिया को धक्का पहुंचाया, के लगभग तीस वर्ष पश्चात सन् 1977 में लंदन के प्रकाशक मैक्मिलन ने मालगांवकर द्वारा किए गए शोधों को 'दि मैन हू किल्ड गांधी' (The man who killed Gandhi) शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित की। उसके कुछ समय पश्चात् मैंने इसे पढ़ा था।

वर्तमान में मेरे सम्मुख इस पुस्तक का 13वां संस्करण है जिसे दिल्ली स्थित रोली बुक्स ने उसी शीर्षक के साथ प्रकाशित किया है परन्तु एक अतिरिक्त उल्लेख के साथ: "अप्रकाशित दस्तावेजों और फोटोग्रास के साथ''। इस संस्करण में, लेखक मालगांवकर अपनी प्रस्तावना में लिखते हैं:

"1960 के दशक के मध्य में, इस अपराध में शामिल कुछ लोगों द्वारा किए गए रहस्योद्घाटनों से लगातार यह आरोप उठ रहे थे कि

संसदीय इतिहास में, पहली बार कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति के कार्यक्रम का बहिष्कार किया। तबसे प्रत्येक 28 मई को वीर सावरकर की जन्मतिथि पर जब सांसद सेंट्रल हॉल में इस महान स्वतंत्रता सेनानी को अपनी श्रद्धांजलि देने आते हैं तो कांग्रेसी सांसद इस कार्यक्रम का बहिष्कार करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी अपने इस व्यवहार पर सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण नहीं दिया है। परन्तु अघोषित कारण यह है कि वह गांधी हत्या केस में एक आरोपी थे। पार्टी इस तथ्य की अनदेखी करती है कि न्यायालय ने इस केस में दो को मृत्युदण्ड और अन्यों को विभिन्न कारावासों की सजा दी थी परन्तु वीर सावरकर को "दोषी नहीं पाया'' और उन्हें बरी किया।

मुंबई में जिम्मेदार पदों पर बैठे अनेक लोगों को इस हत्या की साजिश की पूर्व जानकारी थी, परन्तु वे पुलिस को बताने में असफल रहे। इन आरोपों के पीछे के सत्य को जानने के उद्देश्य से सरकार ने न्यायमूर्ति के.एल. कपूर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग गठित किया। इस आयोग की खोजों की रिपोर्ट को मेरे दोस्त ने मुझे भेजा।

अब मेरे पास आयोग की वृहत और तीक्ष्ण रिपोर्ट थी और मुझे अपनी खोज से न्यायमूर्ति कपूर के निष्कर्षों की प्रमाणिकता सिद्ध करनी थी।

निस्संदेह मैं अभी भी अपनी पुस्तक लिख सकता था। लेकिन मुझे इसमें संदेह था कि कपूर आयोग की रिपोर्ट की सहायता के बगैर 'दि मैन हू किल्ड गांधी' एक मजबूत बन पाती या इतनी चिरकालिक।

पुस्तक पहली बार तब सामने आई जब देश 'आपातकाल' के शिकंजे में था, और पुस्तकों पर सेंसरशिप अत्यन्त निदर्यतापूर्वक लागू थी। इससे मुझ पर यह कर्तव्य आ गया कि जिन कुछ चीजों को मैंने छोड़ दिया था, जैसे डा0 भीमराव अम्बेडकर द्वारा श्री एल0बी0 भोपतकर को दिया गया गुप्त आश्वासन कि उनके मुवक्किल श्री वी0डी0सावरकर को संदिग्ध हत्यारों में कमजोर आधारों पर फंसाया गया। तब फिर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जैसेकि एक मजिस्ट्रेट द्वारा एक गवाही को 'तोड़मरोड़कर' प्रस्तुत करना, जिसकी डयूटी सिर्फ यह रिकार्ड करना थी जो उसे कहा गया है, भी बाद के वर्षों में सामने आई।

इन तथ्यों और अन्य अंशों को उनके सही स्थान पर रखने के बाद मैं महसूस करता हूं कि अब नई पुस्तक महात्मा गांधी की हत्या की साजिश का एक सम्पूर्ण लेखा-जोखा है।

जो भी इस प्रस्तावना को पढ़ेगा तो इसकी प्रशंसा किए बगैर नहीं रह सकेगा कि समूचे राष्ट्र को यह जानना कितना महत्वपूर्ण है कि डा0 अम्बेडकर ने सावरकर के वकील भोपतकर को क्या कहा। इस संदर्भ में मैं पुस्तक के इस संस्करण के सम्बद्ध अंशों को उद्धृत कर रहा हूं:

पुलिस सावरकर को फांसने को क्यों इतनी चिंतित थी? क्या मात्र इसलिए कि गांधी को मारने से पहले वह नाथूराम गोडसे को गिरफ्तार करने का काम नहीं कर पाए थे, इसके चलते अपनी असफलता छुपाने के लिए वह यह बहाना बना रहे थे कि इसके पीछे एक बड़े नेता का हाथ है जो संयोग से उस समय की सरकार की नजरों में खटकता था? या स्वयं वह सरकार या इसमें के कुछ शक्तिशाली समूह, पुलिस एजेंसी का उपयोग कर एक विरोधी राजनीतिक संगठन को नष्ट करना चाहती थी या कम से कम एक प्रखर और निर्भीक विपक्षी हस्ती को नष्ट करना चाहती थी?

या फिर से यह सब भारत, धार्मिकता, वंश, भाषायी या क्षेत्रीयता के विरुद्ध एक अजीब किस्म के फोबिया का प्रकटीकरण था जो समाज के कुछ वर्गों के विष हेतु सावरकर को एक स्वाभाविक निशाना बनाता था?

यह चाहें जो हो, सावरकर स्वयं इसके प्रति सतर्क थे, इतने सावधान भी कि सरकारी तंत्र उन्हें नाथूराम के सहयोगी के रूप में अदालत ले जाएगा कि जब गांधी की हत्या के पांच दिन बाद एक पुलिस दल उनके घर में प्रविष्ट हुआ तो वह उससे मिलने सामने आए और पूछा: "तो आप गांधी हत्या के लिए मुझे गिरतार करने आ गए?" सावरकर को गांधी हत्या केस में एक आरोपी बनाया जाना भले ही राजनीतिक प्रतिशोध का

पुस्तक पहली बार तब सामने आई जब देश 'आपातकाल' के शिकंजे में था, और पुस्तकों पर सेंसरशिप अत्यन्त निदर्यतापूर्वक लागू थी। इससे मुझ पर यह कर्तव्य आ गया कि जिन कुछ चीजों को मैंने छोड़ दिया था, जैसे डा0 भीमराव अम्बेडकर द्वारा श्री एल0बी0 भोपतकर को दिया गया गुप्त आश्वासन कि उनके मुवक्किल श्री वी0डी0सावरकर को संदिग्ध हत्यारों में कमजोर आधारों पर फंसाया गया।

पुलिस सावरकर को फांसने को क्यों इतनी चिंतित थी? क्या मात्र इसलिए कि गांधी को मारने से पहले वह नाथूराम गोडसे को गिरफ्तार करने का काम नहीं कर पाए थे, इसके चलते अपनी असफलता छुपाने के लिए वह यह बहाना बना रहे थे कि इसके पीछे एक बड़े नेता का हाथ है जो संयोग से उस समय की सरकार की नजरों में खटकता था? या स्वयं वह सरकार या इसमें के कुछ शक्तिशाली समूह, पुलिस एजेंसी का उपयोग कर एक विरोधी राजनीतिक संगठन को नष्ट करना चाहती थी या कम से कम एक प्रखर और निर्भीक विपक्षी हस्ती को नष्ट करना चाहती थी?

एक कदम था। हालांकि बडगे का रिकार्ड भी अस्थिर चरित्र वाला और भरोसे करने लायक नहीं था लेकिन वह मुझसे लगातार यह कह रहा था कि उस पर दबाव डालकर झूठ बुलवाया गया और बम्बई के पुलिस विभाग द्वारा उसको माफी तथा भविष्य का खर्चा इस पर निर्भर था कि वह केस में सरकारी दावे का समर्थन करे और विशेषरूप से उसने सावरकर को कभी आपटे से बात करते नहीं देखा, और न ही कभी उन्हें यह कहते सुना: 'यशस्वी हाऊन या।'

केस के सिलसिले में जब भोपतकर दिल्ली में थे तो उन्हें हिन्दू महासभा कार्यालय में ठहराया गया। भोपतकर को यह बात दुविधा में डाल रही थी कि जबकि सभी अन्य आरोपियों के विरुद्ध विशेष आरोप लगाए गए थे परन्तु उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई निश्चित आरोप नहीं थे। वह अपने बचाव पक्ष की तैयारी कर रहे थे कि एक सुबह उन्हें बताया गया कि उनके लिए टेलीफोन आया है, अत: वह सुनने के लिए उस कक्ष में गए जहां टेलीफोन रखा था, उन्होंने रिसीवर उठाया और अपना परिचय दिया। उन्हें फोन करने वाले थे डा. भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने सिर्फ इतना कहा: "कृपया आज शाम को मुझे मथुरा रोड पर छठे मील पर मिलो,'' लेकिन भोपतकर कुछ और कहते कि उधर से रिसीवर रख दिया गया।

केस के सिलसिले में जब भोपतकर दिल्ली में थे तो उन्हें हिन्दू महासभा कार्यालय में ठहराया गया। भोपतकर को यह बात दुविधा में डाल रही थी कि जबकि सभी अन्य आरोपियों के विरुद्ध विशेष आरोप लगाए गए थे परन्तु उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई निश्चित आरोप नहीं थे। वह अपने बचाव पक्ष की तैयारी कर रहे थे कि एक सुबह उन्हें बताया गया कि उनके लिए टेलीफोन आया है, अत: वह सुनने के लिए उस कक्ष में गए जहां टेलीफोन रखा था, उन्होंने रिसीवर उठाया और अपना परिचय दिया। उन्हें फोन करने वाले थे डा. भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने सिर्फ इतना कहा: "कृपया आज शाम को मुझे मथुरा रोड पर छठे मील पर मिलो,'' लेकिन भोपतकर कुछ और कहते कि उधर से रिसीवर रख दिया गया।

उस शाम को जब भोपतकर स्वयं कार चलाकर निर्धारित स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अम्बेडकर पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने भोपतकर को अपनी कार में बैठने को कहा जिसे वह स्वयं चला रहे थे। कुछ मिनटों के बाद, उन्होंने कार को रोका और भोपतकर को बताया: तुम्हारे मुवक्किल के विरूद्ध कोई असली आरोप नहीं हैं, बेकार के सबूत बनाये गये हैं।

केबिनेट के अनेक सदस्य इसके विरूद्ध थे लेकिन कोई फायदा नहीं। यहां तक कि सरदार पटेल भी इन आदेशों के विरुद्ध नहीं जा सके। परन्तु मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कोई केस नहीं है। तुम जीतोगे। "कौन जवाहरलाल नेहरू? लेकिन क्यों?"

मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी के फैसले के बावजूद लोकसभा की अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार अपने कार्यकाल के दौरान इस महान क्रांतिकारी को श्रद्धांजलि देने कई बार आईं। पहले के अपने एक ब्लॉग में मैंने कांग्रेस संसदीय दल से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है।

आजकल श्री शिंदे न केवल गृहमंत्री हैं अपितु लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता भी हैं। मैं चाहता हूं कि सम्माननीय लोकसभाध्यक्ष और श्री शिंदे एक साफ परन्तु गंभीर भूल पर नई पहल करें।

टेलपीस (पश्च्य लेख)

यह पुस्तक पढ़ने से पूर्व मुझे मालूम नहीं था कि कब सावरकर को पुलिस ने 30 जनवरी, 1948 को गांधीजी की हत्या के एकदम बाद बंदी निरोधक कानून के तहत बंदी बनाया था जो "कानून का एक सर्वाधिक विद्वेषपूर्ण अंग है जिसके सहारे ब्रिटिशों ने भारत पर शासन किया।''

बम्बई पुलिस ने शिवाजी पार्क के समीप सावरकर के घर पर छापा मारकर 143 फाइलों और कम से कम 10,000 पत्रों सहित उनके सारे निजी पत्रों को अपने कब्जे में ले लिया।

मालगांवकर लिखते हैं: कहीं भी कोई सबूत नहीं था। जो पता लगा (इन कागजों से) वह था षडयंत्रकारियों का हिन्दू महासभा से सम्बन्ध और सावरकर के प्रति उनकी निजी श्रद्धा।

लेखक निष्कर्ष रूप में लिखते हैं

वह चौंसठ वर्ष के थे और एक वर्ष या उससे ज्यादा समय से बीमार थे। उन्हें 6 फरवरी, 1948 को गिरफ्तार किया गया और पूरे वर्ष जेल में रहे जिसमें जांच और मुकदमा जारी रहे। 10 फरवरी, 1949 को उन्हें 'दोषी नहीं' ठहराया गया।

जो व्यक्ति भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में ब्रिटिश राज में 26 वर्ष जेलों में रहा वह फिर से एक वर्ष के लिए जेल में था वह भी स्वतंत्रता मिलने के तुरंत बाद।'' ■

पूरे भारत में मोदी की महत्वपूर्ण स्थिति

तथागत राय

जादू एक गलत शब्द है, चाहे वह मोदी का हो या किसी और का। राजनीति में बहुत कम चीजें जादू की तरह या जादू के जोर से काम करती हैं। लेकिन यहां सवाल शब्द उत्पत्ति विज्ञान का नहीं है। सवाल यह है कि जब मोदी का जादू फैलने लगेगा तो क्या यह उन राज्यों में भी फैलेगा जहां भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति महत्वपूर्ण स्तर पर नहीं है। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल के तटीय राज्य हैं। सब मिलाकर ये राज्य लोकसभा में लगभग 200 सदस्य भेजते हैं और यह संख्या किसी भी प्रकार कम नहीं है।

इस परिदृश्य में मेरा एक विचार है। भारतीय मतदाता ने अपनी परिपक्वता अनेक बार सिद्ध की है और लोकसभा चुनाव में उसके मतदान का रुझान राज्य विधानसभाओं के उलट रहा है। इसका नवीनतम उदाहरण उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मिलने वाले मत रहे हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में उसे कुल 80 सीटों में से 20 पर विजय मिली, जबकि 2012 के विधानसभा चुनाव में उसे कुल 403 सीटों में से केवल 28 ही प्राप्त हो सकीं। इस तथ्य को देखते हुए कि इस बीच देश भर में कांग्रेस की स्थिति खराब हुई, यह नतीजा निकालने से नहीं बचा जा सकता है कि लोकसभा के लिए मतदान करते समय मतदाता एक अखिल भारतीय पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे थे, जबकि राज्य विधानसभा चुनाव में उसे अस्वीकार कर रहे थे।

इसी प्रकार 1980 में पूरे भारत के मतदाता ने जल्दी से जोड़ कर बनायी गयी जनता पार्टी को अस्वीकार कर दिया था जबकि उसने श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में दोषी होने के बावजूद दृढ़ तथा एकजुट कांग्रेस को सत्ता सौंपी।

तर्क दिया जा सकता है कि मतदाता ने किसी को न चुनकर गलती की और इसके कारण सरकार का गठन एक मजाक बन गया। पहले हमेशा नींद में डूबे रहने वाले देवगौड़ा और बाद में पाकिस्तान-प्रेमी इन्द्र कुमार गुजराल के नेतृत्व में सरकारें बनीं। फिर वर्तमान समय में यह परिघटना क्यों नहीं दुहराई जा सकती है क्योंकि जनता की याददाश्त कम होती है?

अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को स्पष्ट रूप से नरेन्द्र मोदी के सामने उतारेगी या नहीं, हालांकि उन्होंने अपने कार्यों से पहले ही इसके संकेत दे दिये हैं। शायद ही किसी को संदेह हो कि खाद्य सुरक्षा विधेयक, चुनावों पर खर्च किये जाने वाले भारी मात्रा में धन तथा मीडिया के एक हिस्से की भारी वफादारी के बावजूद राहुल गांधी सफल होंगे। वैसे भी, संयोग से मीडिया में ऐसे हिस्से के कुछ लोग उसी प्रकार के अवसरवादी हैं जैसे डूबते जहाज को छोड़ कर भागने वाले चूहे। इसलिये मतदाता को संभवत: मोदी नीत राजग तथा 1996 में मची अव्यवस्था के बीच चुनाव करना होगा।

इसलिये यह तर्क दिया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में मतों का विभाजन माकपा व ममता बनर्जी के बीच, तमिलनाडु में द्रमुक एवं अन्ना द्रमुक के बीच तथा केरल में यूडीएफ व एलडीएफ के बीच क्यों नहीं होगा और ओडिशा में सारे वोट बीजद के नवीन पटनायक के पक्ष में क्यों नहीं चले जायेंगे। लेकिन आंध्र प्रदेश में क्या होगा? राजनीतिक टिप्पणीकार इसे बहुत 'पेचीदा सवाल' मानते हैं। तेलंगाना के नाम पर कांग्रेस ने मतदाताओं को अपने

भारतीय मतदाता ने अपनी परिपक्वता अनेक बार सिद्ध की है और लोकसभा चुनाव में उसके मतदान का रुझान राज्य विधानसभाओं के उलट रहा है। इसका नवीनतम उदाहरण उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मिलने वाले मत रहे हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में उसे कुल 80 सीटों में से 20 पर विजय मिली, जबकि 2012 के विधानसभा चुनाव में उसे कुल 403 सीटों में से केवल 28 ही प्राप्त हो सकीं। इस तथ्य को देखते हुए कि इस बीच देश भर में कांग्रेस की स्थिति खराब हुई, यह नतीजा निकालने से नहीं बचा जा सकता है कि लोकसभा के लिए मतदान करते समय मतदाता एक अखिल भारतीय पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे थे, जबकि राज्य विधानसभा चुनाव में उसे अस्वीकार कर रहे थे।

साथ लाने का प्रयास किया है, पर वह उसमें विफल हो गयी है। इसके साथ ही साथ उसने सीमान्ध्रा, अर्थात तटीय आन्ध्र एवं रायसीमा में मतदाताओं को अपने से दूर कर दिया है। ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि आंध्र प्रदेश में वोटों का विभाजन चन्द्रबाबू नायडू की तेलगू देशम पार्टी तथा जगन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस के बीच क्यों नहीं होगा। इससे कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हो जायेगी और उसे बचे-खुचे टुकड़ों से ही संतोष करना पड़ेगा।

यह सारी चीजें या इनमें से कोई परिघटना क्यों नहीं सामने आ सकती है? यदि ऐसा होता है तो 1996 जैसी अव्यवस्था क्यों नहीं पैदा हो सकती है? ऐसा होने पर शायद एक ही साल में पुन: चुनाव की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।

मेरा मानना है कि दो कारणों से इन परिदृश्यों के उभरने की कोई खास संभावना नहीं है। पहला, भले ही जनता की याददाश्त छोटी होती हो और इस बारे में कोई संदेह न हो, पर कुछ तबकों में यह बची भी रहती है या उसके कुछ अंश लोगों के दिमाग में ताजा बने रहते हैं।

दूसरा कारण यह है कि इस बार मतदाताओं में भारी संख्या युवाओं की होगी तथा जनता का मीडिया से संपर्क पहले की तुलना में अनेकों गुना बढ़ गया है। मेरा तर्क है कि इन दोनों के संयुक्त प्रभाव से 1996 जैसी अव्यवस्था तथा मोदी नीत राजग के बीच चुनाव करने के मामले में मतदाताओं का झुकाव मोदी के पक्ष में बहुत अधिक हो जायेगा।

यदि वर्तमान परिदृश्य को थोड़ा अलग तरीके से देखा जाये तो 1996 जैसी अव्यवस्था की स्थिति बनने पर अलग-अलग पक्षों को व्यक्तिगत स्तर पर देखा जाना चाहिये।

लोकसभा में बैठे ममता बनर्जी के सांसद केवल इतना ही कर सकते हैं कि उनसे सेलफोन पर अपने काम के बारे में निर्देश प्राप्त करें और बाकी समय हाथ मलते रहें। हालांकि एक संभावना यह भी हो सकती है कि स्वयं ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में शामिल हो जायें। वास्तव में इसका परिणाम बहुत दिलचस्प होगा। बीजू जनता दल के पास मध्यम स्तर तक सक्षम तथा स्वच्छ सांसद बैजयन्त पांडा हैं, लेकिन वे बस एक अपवाद हैं। बाकी लोगों में ए. राजा, कनिमोझी, मुलायम सिंह यादव और राम विलास पासवान शामिल हैं। इनमें लालू प्रसाद यादव भी शामिल हैं बशर्ते इस बीच वे चारा घोटाले में जेल न चले जायें। इनमें से प्रधानमंत्री कौन बनेगा? उसका चुनाव कैसे होगा? वह कब तक सत्ता में बना रहेगा?

मेरा तर्क है कि निश्चित रूप से मैं अकेला ऐसा आदमी नहीं हूं जिसके सामने ये सारे सवाल खड़े होते हैं। ये सारे सवाल सभी औसत मतदाताओं के सामने खड़े होते हैं, किसी के सामने थोड़ा कम तो किसी के सामने थोड़ा ज्यादा। किसी के सामने ये सवाल सुसंगत रूप से आते हैं तो किसी के सामने अस्पष्ट रूप से। इन लोगों में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु व केरल के अधिकांश औसत मतदाता शामिल हैं। अतीत में मतदाताओं ने अपने साथ जिस प्रकार का पक्षपात देखा है उसे गौर करते हुए शायद ही अब कोई समझदार मतदाता 1996 में पैदा अव्यवस्था जैसा विकल्प चुनना पसंद करे।

दूसरे शब्दों में जिन लोगों ने अब तक भाजपा को वोट नहीं दिया होगा इस बार परिस्थितियों को देखते हुए वे भी उसे वोट दे सकते हैं। इसका पहला कारण यह है कि भाजपा को मोदी का नेतृत्व मिल रहा है जो दृढ़ है, अपनी क्षमता सिद्ध कर चुका है तथा भविष्य की ओर देखने वाला है। दूसरा कारण यह भी है कि कोई दूसरा व्यक्ति वोट देने योग्य नहीं है। ■

(साभार- पायनियर)

मेरा तर्क है कि निश्चित रूप से मैं अकेला ऐसा आदमी नहीं हूं जिसके सामने ये सारे सवाल खड़े होते हैं। ये सारे सवाल सभी औसत मतदाताओं के सामने खड़े होते हैं, किसी के सामने थोड़ा कम तो किसी के सामने थोड़ा ज्यादा। किसी के सामने ये सवाल सुसंगत रूप से आते हैं तो किसी के सामने अस्पष्ट रूप से। इन लोगों में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु व केरल के अधिकांश औसत मतदाता शामिल हैं। अतीत में मतदाताओं ने अपने साथ जिस प्रकार का पक्षपात देखा है उसे गौर करते हुए शायद ही अब कोई समझदार मतदाता 1996 में पैदा अव्यवस्था जैसा विकल्प चुनना पसंद करे। दूसरे शब्दों में जिन लोगों ने अब तक भाजपा को वोट नहीं दिया होगा इस बार परिस्थितियों को देखते हुए वे भी उसे वोट दे सकते हैं।

सांप्रदायिकता की प्रतिस्पर्धा

✍ हृदयनारायण दीक्षित

लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनावी ताप के साथ सांप्रदायिक उत्ताप भी बढ़ रहा है। राष्ट्रीय मुद्दे ढेर सारे हैं। देश की अर्थव्यवस्था वित्तीय आपातकाल जैसी है। भ्रष्टाचार संस्थागत हुआ है। महंगाई लगातार बढ़ी है। विकास दर घटी है। पड़ोसी देश कमजोर केंद्र पाकर आंख दिखा रहे हैं। नक्सली हिंसा बढ़ी है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अकर्मण्य वीतरागी सिद्ध हो चुके हैं। दलतंत्र के पास ऐसे ही अनेक मुद्दे हैं, लेकिन चुनावी राजनीति सांप्रदायिक हो रही है। सभी दलों को असांप्रदायिक मुद्दे ही उठाने चाहिए, लेकिन संप्रग और कथित सेक्युलर दल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के सहारे वोट पाने का खतरनाक खेल खेल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ विधानसभाओं के चुनाव हैं, लेकिन राष्ट्रीय एकता का रासायनिक संगठन गड़बड़ा गया है। मुजफ्फरनगर की आंच पूरे देश तक पहुंची है। मध्य प्रदेश में इंदौर, बिहार में नवादा, बेतिया, जम्मू में किश्तवाड़, असम में सिलचर में सांप्रदायिक हिंसा हुई है। बावजूद इसके राजनीति सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का रासायनिक हथियार लेकर युद्धरत है।

अंग्रेजीराज भी सांप्रदायिक हथियारों से खेल रहा था। 1929 में डॉ. अंबेडकर ने लिखा था कि एक सामान्य राष्ट्रभाव जगाना इस समय बहुत जरूरी है। यह भाव कि वे सबसे पहले भारतीय हैं उसके बाद हिंदू मुसलमान। संविधान में हिंदू मुसलमान अलग इकाई नहीं है, लेकिन राजनीति सांप्रदायिक भावना को ही भड़काती है। माना जाता है कि मुसलमान थोक वोट देते हैं इसलिए उन्हें रिझाने की कोशिशें अलग से की जाती हैं। लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 218 पर मुस्लिम आबादी लगभग 10 प्रतिशत है। 30 से 35 सीटों पर वे लगभग 30 प्रतिशत है। 38 सीटों पर यह 21 से 28 प्रतिशत तक है। थोक वोट के कारण उनके मत निर्णायक हो जाते हैं। इसीलिए सांप्रदायिक तुष्टीकरण की प्रतिस्पर्धा है। उन्हें अलग 'लाभार्थी समूह' बनाने की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी बढ़ी है। सांप्रदायिकता रासायनिक हथियार है। भारत का विभाजन सांप्रदायिक अलगाववाद से ही हुआ था।

सांप्रदायिकता राष्ट्रतोड़क है और राष्ट्रद्रोह भी। सरकारें मजहबी आधार पर विकास कार्य और अन्य सहूलियतों का वोट बैंक उपहार देती हैं। पश्चिम बंगाल ने इमामों व मुअज्जिनों के लिए मानदेय व उत्तर प्रदेश ने योजनाओं में मुस्लिम समुदाय के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण, कब्रिस्तानों की बाउंड्री के लिए 300 करोड़ की धनराशि और आतंकी आरोपियों के भी मुकद्दमा वापसी के प्रस्ताव किए। दिल्ली सरकार ने वक्फ बोर्ड के इमामों, मुअज्जिनों के लिए मानदेय की घोषणा की। केंद्र मुस्लिम बहुल जिलों के विकास की योजना पर सक्रिय था ही अब मुस्लिम बहुल गांवों का सर्वेक्षण होने जा रहा है। सांप्रदायिक निर्णयों, आश्वासनों से धुव्रीकरण का ताप बढ़ा है। कोढ़ में खाज यह है कि ऐसी तमाम सांप्रदायिक सहूलियतों के बावजूद मुसलमानों में असुरक्षा का भाव भी भड़काया जा रहा है। कथित सेक्युलरों में खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा सुरक्षा गार्ड बताने की प्रतिस्पर्धा है। यह प्रतिस्पर्धा मोदी को सामने पाकर तेज रफ्तार बढ़ी है। संभावित मोदीराज को भयावह बताकर काल्पनिक खौफ पैदा किया जा रहा है।

सांप्रदायिक उपकरणों से असांप्रदायिक समाज नहीं बनते। मुलायम

सभी दलों को असांप्रदायिक मुद्दे ही उठाने चाहिए, लेकिन संप्रग और कथित सेक्युलर दल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के सहारे वोट पाने का खतरनाक खेल खेल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ विधानसभाओं के चुनाव हैं, लेकिन राष्ट्रीय एकता का रासायनिक संगठन गड़बड़ा गया है। मुजफ्फरनगर की आंच पूरे देश तक पहुंची है। मध्य प्रदेश में इंदौर, बिहार में नवादा, बेतिया, जम्मू में किश्तवाड़, असम में सिलचर में सांप्रदायिक हिंसा हुई है। बावजूद इसके राजनीति सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का रासायनिक हथियार लेकर युद्धरत है।

सिंह ने सांप्रदायिक उपकरणों से ही अपनी लोकप्रियता बढ़ाई थी। उन्होंने समाज का रासायनिक संगठन तोड़ा। मुजफ्फरनगर के ताजा दंगे सहित 100 से ज्यादा वारदातें हो गईं। सांप्रदायिक राजनीति का रासायनिक हथियार उनके ही गले की फांसी है। मुसलमान भी उनसे नाराज हैं। भाजपा को मुस्लिम विरोधी कहा जाता है। भाजपा ने बारी-बारी से देश के लगभग एक दर्जन राच्यों में प्रतिष्ठित सरकारें चलाई हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के छह वर्षीय राज में मुसलमानों पर क्या संकट आया? भाजपा पंथ, मजहब के आधार पर विशेषाधिकार के विरुद्ध है। इसी बात को लेकर गैरभाजपा दल भाजपा पर सांप्रदायिकता के आरोप लगाते हैं और उसे मुसलमानों का शत्रु बताते हैं। आखिरकार केंद्रीय सत्ता का दावेदार और केंद्रीय सत्ता का अनुभवी राष्ट्रीय दल 18 करोड़ भारतवासियों को अपना शत्रु कैसे मान सकता है? भाजपा उन्हें सभी भारतवासियों जैसा भारतीय ही जानती है, लेकिन कथित सेक्युलर उन्हें सांप्रदायिक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं।

सांप्रदायिकता अब युद्धरत है। कथित सेक्युलर दलों ने इसे युद्ध पिपासु बनाया है। सांप्रदायिक आधार पर सहूलियतों की राजनीति समाजतोड़क है। 1991 में दसवीं लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस व जद ने अपने घोषणापत्रों में अन्य नौकरियों के साथ सैन्यबलों में भी मजहबी आरक्षण का वायदा किया था। केरल और बिहार में मुस्लिम बहुल आबादी के आधार पर जिले बनाने की घटनाएं भी आत्मघाती थीं। मूलभूत प्रश्न है कि संप्रदाय विशेष की आबादी के आधार पर जब विशेष सुविधाएं दी जा सकती हैं या जिले बनाए जा सकते हैं? तो ऐसा कृत्य अलग राज्य या अलग देश की मांग की बुनियाद क्यों नहीं है? यह अलगाववाद को बढ़ावा नहीं तो और है क्या? लेकिन हमारी चुनावी राजनीति के एजेंडे में राष्ट्र का सशक्तिकरण कोई मुद्दा नहीं है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता का कोई विचार नहीं।

चुनाव जीत ही लक्ष्य है। खून बहे, तो बहे। सामाजिक सद्भाव टूटे तो टूटे। सांप्रदायिक राजनीति के सौदागर नहीं मानते कि सांप्रदायिक उन्माद से मिली सत्ता को चलाने के लिए भी सांप्रदायिक नीति पर ही चलने की विवशता होती है। मुलायम सिंह की राजनीति इसी की ताजा मिसाल है।

मुजफ्फरनगर दंगे में पीड़ितों के पास प्रधानमंत्री गए और मुख्यमंत्री भी, लेकिन बाकी दलों के नेता क्यों रोके गए? अच्छा तो यह होता कि सर्वदलीय नेतृत्व जाता। सामूहिक रूप में सामाजिक सद्भाव की अपील करता। लेकिन शवों का अंतिम संस्कार भी पूरा नहीं हुआ और इस दल ने उस दल पर या उस दल ने इस दल पर दंगों की तोहमत लगा दी। आरोप-प्रत्यारोप बाद में भी हो सकते हैं। वोट गणित जारी है, एक संप्रदाय के ध्रुवीकरण से उसको फायदा होगा और दूसरे से उसको। इसको बिल्कुल घाटा होगा। हिंसा, रक्तपात और शव संस्कार के करुण रुदन के बीच वोट गणित और समीकरण की बेचैनी आश्चर्यचकित करने वाली है। राष्ट्रीय बेचैनी यह है कि क्या लोकसभा के चुनाव सांप्रदायिक उन्माद के बारूदी टैंक लेकर ही लड़े जाएंगे? चुनाव आयोग को सभी दलों की बैठक बुलानी चाहिए।

दलों को बाध्य किया जाना चाहिए कि वे सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति से बाज आएं। सांप्रदायिक आधार पर कोई वायदे न हों। दल आत्मनिरीक्षण करें कि सांप्रदायिकता राष्ट्रतोड़क है। देश ही नहीं बचेगा तो राजनीति कहां और कैसे होगी? ■

(लेखक उप्र विधानपरिषद के सदस्य हैं)

भाजपा ने बारी-बारी से देश के लगभग एक दर्जन राच्यों में प्रतिष्ठित सरकारें चलाई हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के छह वर्षीय राज में मुसलमानों पर क्या संकट आया? भाजपा पंथ, मजहब के आधार पर विशेषाधिकार के विरुद्ध है। इसी बात को लेकर गैरभाजपा दल भाजपा पर सांप्रदायिकता के आरोप लगाते हैं और उसे मुसलमानों का शत्रु बताते हैं। भाजपा उन्हें सभी भारतवासियों जैसा भारतीय ही जानती है, लेकिन कथित सेक्युलर उन्हें सांप्रदायिक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं।

मुजफ्फरनगर दंगे में पीड़ितों के पास प्रधानमंत्री गए और मुख्यमंत्री भी, लेकिन बाकी दलों के नेता क्यों रोके गए? अच्छा तो यह होता कि सर्वदलीय नेतृत्व जाता। सामूहिक रूप में सामाजिक सद्भाव की अपील करता। लेकिन शवों का अंतिम संस्कार भी पूरा नहीं हुआ और इस दल ने उस दल पर या उस दल ने इस दल पर दंगों की तोहमत लगा दी। आरोप-प्रत्यारोप बाद में भी हो सकते हैं। वोट गणित जारी है, एक संप्रदाय के ध्रुवीकरण से उसको फायदा होगा और दूसरे से उसको।

'जन आशीर्वाद यात्रा' पर विशेष

विकास पथिक की झोली में आशीर्वाद की सौगात

✍ भरतचंद्र नायक

आदि शंकराचार्य ने देशाटन कर सांस्कृतिक जागरण की मुहिम चलायी। लगता है कि यही से देश में यात्राओं की परंपरा की बीजांकुर पड़ा। आज भी विभिन्न अंचलों में यात्राएं अपने आंचलिक रूपांतर में विद्यमान है। स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरूषों ने जनमानस में पैठ बनाने और जनमानस को समझने राष्ट्रीय स्वाभिमान जाग्रत करने के लिए देशाटन किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वाधीनता आंदोलन का सूत्रपात इसी तरह की यात्राओं को माध्यम बनाकर किया। सांस्कृतिक एकता के सूत्र में गुंफित करने के इन्हीं प्रयासों को विभिन्न रूपों में रामरथ यात्रा, जनादेश यात्रा, भारत सुरक्षा यात्रा, भ्रष्टाचार के विरूद्ध जनमानस बनाने के लिए निकाली गयी यात्रा के रूप में याद किया जाता है। मध्यप्रदेश में जब से विकास राजनीति का अंग बनी भारतीय जनता पार्टी ने इस परम्परा को सामाजिक सरोकार का रूप दिया है। भाजपा ने 2008 में प्रदेश में पांच वर्षो में बुने गए विकास के ताना बाना का मूल्यांकन जनता के बीच पहुंचकर करने के अपने विनम्र प्रयासों के तहत जन आशीर्वाद यात्रा आयोजित की थी। इसका नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान ने ही किया था, लेकिन इस बार 22 जुलाई से प्रदेशव्यापी आरंभ जन आशीर्वाद यात्रा को जिस गर्मजोशी के साथ जनता का समर्थन मिल रहा है शिवराज सिंह चौहान जनमानस पर विकास यात्री की छवि अंकित करने में सफल हो रहे हैं। मतभिन्नता स्वाभाविक है। कुछ इसे सियासी कसरत, चुनावी के रूप में देखते हैं कदाचित वे इस यात्रा से जुड़े सामाजिक सरोकार को या तो समझ नहीं पा रहे हैं अथवा जानबूझकर सियासी नजरिये में ही उलझकर रह गये हैं।

22 जुलाई से प्रदेशव्यापी आरंभ जन आशीर्वाद यात्रा को जिस गर्मजोशी के साथ जनता का समर्थन मिल रहा है शिवराज सिंह चौहान जनमानस पर विकास यात्री की छवि अंकित करने में सफल हो रहे हैं।

वैसे यदि सियासी नजरिये से ही देखा जाए तो मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जारी 50 दिवसीय जन आशीर्वाद यात्रा के समानान्तर आयोजित की गयी कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का भी उल्लेख किया जाना समीचीन होगा। इसका नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया कर रहे हैं जिन्हें कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया का संरक्षण और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का प्रोत्साहन मिल रहा है, लेकिन परिवर्तन यात्रा न तो प्रदेश में जनता के बीच छवि छोड़ पायी है और न इसे पार्टी संगठन का पुरजोर समर्थन ही मिला है जबकि इस दृष्टि से जन आशीर्वाद यात्रा विपरीत ध्रुव पर विशिष्ट पहचान और लोकप्रियता हासिल कर रही है। राजनैतिक विश्लेषकों का मानना है कि जन आशीर्वाद यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी ने 2003 में जनादेश पाने के बाद 2008 में उस मिथक को झूठ साबित किया कि भाजपा दूसरी बार सत्ता में नहीं आती। अब उसका लक्ष्य मिशन 2013 की सफलता पर केन्द्रित है और वह अपनी उपलब्धियां जनता की अदालत में प्रस्तुत करके जनता से विजय का आशीर्वाद की अपेक्षा लिए हुए जनता का कंठहार बन रही है। प्रदेश में हुई 40 जनपंचायतों ने जनजीवन के हर क्षेत्र और आम आदमी से जुड़े पहलुओं पर विचार कर समाधानकारक सुझाव मुख्यमंत्री निवास पर दिए जिस पर नीति का निर्धारण हुआ और अमल होते भी जनता देख चुकी है। इन जनपंचायतों ने लोकतंत्र की उस परिभाषा को चरितार्थ किया है जो बताती है ''जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार'' जनपंचायतों का यही निहितार्थ रहा है। जनता में बनी इसी अवधारणा ने जन-जन को अभिभूत किया है और न केवल इस सफलता ने राज्य सरकार को सराहा है अपितु जनसेवक के रूप में शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता का ग्राफ शिखर पर पहुंचा है। मुख्यमंत्री प्रदेश का राजा नहीं सूबे की जनता का प्रथम सेवक है, ऐसा आम आदमी ने महसूस किया है। दूसरी ओर परिवर्तन यात्रा पर निगाह डालें तो प्रदेश का आम आदमी 2003 में मध्यप्रदेश बीमारू राज्य की बदहाली को भूल नहीं पा रहा है। जब वह कांगेस की परिवर्तन की चाहता पर विचार

करता है वह मौजूदा निजाम में परिवर्तन की कल्पना को प्रदेश का बंटाधार शासन में लौटने की कल्पना के दु:स्वप्न से सिहर उठता है। इसी का परिणाम है कि जन आशीर्वाद यात्रा जहां जनसैलाब के आकर्षण का केन्द्र बन चुकी है वहीं कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा प्रदेश में अपशगुन के रूप में देखी जा रही हैं इन यात्राओं में एक स्पष्ट अंतर यही दिखायी होता है कि दो विपरीत दृष्टिकोण दृष्टिगोचर होते हैं। जन आशीर्वाद यात्रा विकास का उजला पक्ष पेश करती है वहीं परिवर्तन यात्रा व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से आरंभ होकर सत्ता की चाहता की अपील के साथ ओझल हो रही है। 'जनआशीर्वाद यात्रा' जहां सकारात्मक संवाद है वहीं 'परिवर्तन यात्रा' कांग्रेस की सियासी आकस्मिकता मात्र है जो मानमानस को न तो गुदगुदा पाती है और न आश्वस्त करती है। वहां न तो कोई कार्ययोजना है और न विकास का दृष्टिपत्र है जबकि दूसरी ओर फसाना नहीं हकीकत है।

महज आंकड़े नहीं धरातल पर दिखने वाली तरक्की है। इस दौरान यदि तरक्की हुई है तो खासोआम के चेहरे पर मुस्कान प्रफुल्लता है। गांवों की पगडंडियां इससे बयान करती है। शिवराज सिंह चौहान ने नेतृत्व में जन आशीर्वाद यात्रा प्रदेश के कमोवेश सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों का स्पर्श करती हुई 27 अक्तूबर तक राज्य की परिक्रमा कर रही है। यात्रा का शिल्प पार्टी के शीर्ष नेतृत्व विशेष रूप से पार्टी अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रभात झा, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री अरविन्द मेनन और वरिष्ठ नेता अनिल माधव दवे ने टीम भावना से विकसित किया है जो दिन प्रतिदिन के घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में जनता को भा रहा है। शिवराज सिंह चौहान का किसान पुत्र का सहज सरल मानस, विनम्रता और स्पष्टवादिता जन-जन को आकर्षित किए बिना नहीं रहती, यही कारण है कि जब प्रदेश बारिश की अभूतपूर्व झड़ी में लथपथ भीग रहा है। भारी बारिश पानी के बीच रात्रि को 2 बजे तक जन आशीर्वाद यात्रा की सभाओं और शिवराज सिंह चौहान से संवाद करने के लिए गांवों में भीड़ उमड़ती दिखायी देती है। शिवराज सिंह चौहान भी दिनभर की भारी मशक्कत के बावजूद तरोताजा जन-जन से स्नेहपूर्वक संवाद करने का व्यामोह छोड़ नहीं पाते। मुख्यमंत्री और जनता के बीच यह रागात्मक संबंध और लगाव देखकर लगता है कि क्या एकात्म मानवदर्शन इससे विलग है? शिवराज की गांव गंवई ठेठ भाषा में लोकोक्तियां हंसी का फव्वारा तो छोड़ती है, यथार्थोन्मुख आदर्शवाद की भी झलक मिलती है। स्नेह कभी एकांगी नहीं होता यह जन आशीर्वाद यात्रा का मर्म और चरम है।

जन आशीर्वाद यात्रा टुकड़ों-टुकड़ों में किए जाने के पीछे मुख्यमंत्री की प्रदेश की जनता के प्रति प्रतिबद्धता दिखायी देती है कि वे प्रदेश के हालात, दैनंदिन जीवन की समस्याओं और सरकारी प्रतिबद्धता से बेखबर नहीं रहना चाहते। रोजमर्रा के सरकारी कामकाज से रूबरू होने के लिए राजधानी में मौजूद रहकर शासन का नेतृत्व करना नहीं भूल रहे। जन आशीर्वाद यात्रा मोटर वाहनों (दो) पर बने रथ से जारी है जो प्रदेश की लंबाई चौड़ाई नापती हुई करीब 8000 कि.मी. का सफर पूरी करेगी और प्रदेश के सवा सात करोड़ जनता का प्रतीकात्मक आशीर्वाद प्राप्त करने का अपना लक्ष्यपूर्ण करेगी। वे जनता से स्वर्णिम मध्यप्रदेश का आगाज करते हैं और यह भी कहना नहीं भूलते कि आने वाले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश देश का अव्वल दर्जे का विकसित राज्य होगा। इस अनुष्ठान में जन-जन के समर्थन की आहुति नवंबर के चुनाव में पड़ेगी। तभी मिशन 2013 जनसहयोग और समर्थन से सफल होगा।

''राम की चिरैया, राम का खेत''

जन आशीर्वाद यात्रा में जमा हो रही कस्बायी, नगरी और देहाती क्षेत्रों की भीड़ राजनीति के इस दौर में जहां राजनीति पर नाक-मुंह सिकोड़ना आम बात बन चुकी है, सभी को विस्मित करती है। विपक्षी दल राजेबरोज यात्रा को मजाक, तमाशा और नौटंकी बताकर हंसी उड़ा रहा है, लेकिन यात्रा में जन सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा है। समाज का हर तबका कोटवार, मेहनतकश, मजदूर, युवा, महिला, किसान, वनवासी, दलित, अल्पसंख्यक, बाल-वृद्ध क्यों जुट रहे हैं यह सवाल विचारकों के माथे पर सिकुड़न लाता है? कदाचित वे भूल जाते हैं कि आजादी के बाद पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने जनता और शासन की दूरियों को संवाद से पाटा है, उनकी मुरादें पूरी की हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान तमाम औपचारिकताओं को तिलांजलि देकर जन-जन को गले लगा लेते हैं। जनता जहां उन्हें जी भरकर आशीर्वाद देती है वहीं शिवराज कहते हैं कि मध्य प्रदेश के खजाने पर राजनेताओं का नहीं गांव, गरीब, मेहनतकश का अधिकार है। 9 वर्षों में कोई नया टैक्स लगा नहीं। राजस्व, शुल्क वसूली की हेराफेरी बंद होने से प्रदेश की आय चौगुनी बढ़ी है। भाजपा सरकार की अवधारणा में वही सनातन तत्व विद्यमान हैं ''राम की चिरैया राम का खेत, खावो चिरैया भर-भर पेट'' तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा। ■

छत्तीसगढ़ : पं. दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर संगोष्ठी

संसाधनों पर गरीब व्यक्ति का पहला अधिकार : डॉ रमन सिंह

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने 25 सितम्बर को रायपुर स्थित नवीन विश्राम भवन में एकात्म मानववाद के प्रवर्तक पं. दीनदयाल उपाध्याय की 97 वीं जयंती के अवसर पर 'भारत के पुनरूत्थान का मार्ग: एकात्म मानवदर्शन की प्रासंगिकता' विषय पर आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया। संगोष्ठी का आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर के पं. दीनदयाल उपाध्याय मानव अध्ययन शोध पीठ द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के जनजीवन में संत कबीर के व्यापक प्रभाव को देखते हुए रायपुर के कुशाभाऊ पत्रकारिता विश्वविद्यालय में संत कबीर विकास संचार अध्ययन केन्द्र प्रारंभ करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पं. दीनदयाल शोधपीठ द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'विकास और विकेन्द्रित अर्थचिन्तन' का विमोचन भी किया। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री श्री चंद्रशेखर साहू, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सच्चिदानंद जोशी और पं. दीनदयाल उपाध्याय मानव अध्ययन शोध पीठ के अध्यक्ष श्री दिनकर केशव भाकरे भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्य अतिथि की आसंदी से संगोष्ठी में डॉ. रमन सिंह ने कहा कि पंडित दीनदयाल जैसे महामानव का चिंतन कालजयी था। भारत की हजारों साल पुरानी सनातन परम्परा को दिल में रखकर वे सैकड़ों साल आगे देश के भविष्य के बारे में सोचते थे। श्री उपाध्याय ने अपने जीवनकाल में देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर यहां के लोगों को नजदीक से देखा और समझा। भारत सहित पूरे विश्व में प्रचलित तत्कालीन राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं का उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया और इन सबके निचोड़ के रूप में 'अंत्योदय' का विचार प्रस्तुत किया। उनके अनुसार राज्य की संसाधनों पर गरीब व्यक्ति का पहला अधिकार होना चाहिए। जाति, वर्ग और धार्मिक भेद-भाव के बगैर गरीबों का सर्वांगीण विकास किसी भी राज्य सरकार का लक्ष्य होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की सरकार उनके अंत्योदय विकास को आदर्श मानकर गरीबों को समाज की मुख्यधारा में लाने का कार्य कर रही है। वंचित और उपेक्षित तबके के इन लोगों को केन्द्र बिन्दु मानकर उन्हें स्वास्थ्य, भोजन शिक्षा और रोजगार की सुविधाएं मुहैया करा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करते समय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल विहारी वाजपेयी ने जो सपना संजोया था, उस सपने को पं. दीनदयाल के बताए मार्ग पर चलकर पूरा करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब व्यक्ति को केवल भोजन ही नहीं बल्कि पोषणयुक्त भोजन का अधिकार हमने दिया है। चावल के साथ उन्हें अब हम प्रोटीनयुक्त दाल, आयोडिनयुक्त नमक और चना भी उपलब्ध करा रहे हैं। कुपोषण की दर में कमी होने के साथ आईएमआर और एमएमआर की दर में यहां उल्लेखनीय कमी आई है। समाज में अंत्योदय समूह को लक्षित करके हमने '102' और '104' नि:शुल्क एम्बुलैंस सेवाएं शुरू की हैं। पूरे राज्य के लिए हमने काफी मेहनत करके यह व्यवस्थाएं तैयार की हैं। डॉ. सिंह ने कहा कि राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए हमने योजनाबद्ध प्रयास किए हैं। गांव के अकुशल लोगों की क्षमता और कौशल विकास के लिए उन्हें चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। तीन-चार माह के प्रशिक्षण में हम उन्हें इतना दक्ष बना देते हैं कि वे अपने पैरों पर खड़े होकर आमदनी प्राप्त करने लगते हैं। नक्सल हिंसा से प्रभावित लोगों को हमने राजधानी में 'प्रयास' स्कूलों के जरिए पढ़ाई और कोचिंग की उत्तम व्यवस्था की है। प्रयास के बच्चे आज देश के प्रतिष्ठित आई.आई.टी, एनआईटी और मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेकर प्रदेश को गौरवान्वित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेती-किसानी के लिए दी जा रही

ब्याज की दर सोलह प्रतिशत से घटाकर मात्र एक प्रतिशत की गयी है, इसका यह प्रभाव हुआ कि सहकारी समितियों से अब दो हजार करोड़ रुपए तक ऋण किसान ले रहे हैं। जबकि आज से दस साल पहले मात्र डेढ़ सौ करोड़ ऋण ली जाती थी।

कृषि मंत्री श्री चंद्रशेखर साहू ने अपने उद्बोधन में कहा कि महात्मा गांधी के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ही देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को अच्छी तरह समझा था। समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को सामने लाने का उन्होंने भरपूर प्रयास किया। श्री साहू ने कहा कि देश में एक बार ऐसी स्थिति थी कि देश के प्रधानमंत्री को भोजन बचाने के लिए उपवास रखने की अपील करनी पड़ी किन्तु आज ऐसी स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी ओर से लोगों को दोनो समय भोजन उपलब्ध करा रही है। श्री साहू ने कहा कि पं. दीनदयाल उपाध्याय के बताए मार्ग पर चलकर राज्य सरकार वनवासी, गरीब, मजदूर, किसान और युवाओं को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने का योजनाबद्ध प्रयास कर रही है।

संगोष्ठी में दिल्ली से आए भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक डॉ. आर. बालाशंकर ने प्रमुख वक्तव्य दिया। उन्होंने देश की बदलती अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत विचार व्यक्त किए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्वेदशी जागरण मंच के संगठक श्री कश्मीरी लाल, डॉ. आर. बालाशंकर और संपादक श्री राजेन्द्र शर्मा का आयोजन समिति की ओर से सम्मानित किया। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति श्री सच्चिदानंद जोशी ने आभार व्यक्त किया। ■

पूर्वोत्तर के लोगों तक भाजपा की विचारधारा का संदेश पहुंचे : राजनाथ सिंह

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह द्वारा पूर्वोत्तर के दौरे पर 19 सितम्बर 2013 को जारी वक्तव्य

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राजनाथ सिंह ने 18 सितम्बर को पूर्वोत्तर भारत के दो दिवसीय दौरे पर असम पहुंचे। उनके साथ राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) श्री रामलाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं असम के प्रभारी श्री एस. एस. अहलूवालिया तथा अन्य राष्ट्रीय पदाधिकारी भी थे और उन्होंने आगामी लोकसभा चुनावों तथा पूर्वोत्तर में सामान्य राजनीतिक स्थिति पर पूर्वोत्तर के सभी सातों राज्यों के साथ व्यापक एवं विस्तृत चर्चा की। 18 सितम्बर को उन्होंने नागालैण्ड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोराम के साथ लम्बी बैठकें आयोजित की गई।

19 सितम्बर को अरूणाचल प्रदेश और असम के नेताओं के साथ चर्चा हुई।

राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) श्री रामलाल ने वर्तमान संगठनात्मक गतिविधियों को बढ़ाने पर बल दिया तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री एस.एस. अहलूवालिया ने पार्टी की विचारधारा और नीतियों को लोगों तक पहुंचाने में कार्यकर्ताओं से आग्रह किया।

माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने कार्यकर्ताओं से मूल्याधारित राजनीति अपनाने का अग्रह किया और उनसे भाजपा का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए कहा। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था की बिगड़ती हालत पर अपनी चिंता व्यक्त की तथा उन्होंने यूपीए सरकार द्वारा लोगों के जख्मों के प्रति लापरवाही की भर्त्सना की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को स्मरण कराया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र भाजपा के लिए सदैव उसी प्रकार प्राथमिकता बनी रहेगी जैसी कि विगत एनडीए सरकार के शासन काल में थी जब इस सरकार ने पूर्वोत्तर के सभी मंत्रालयों के लिए 10 प्रतिशत का धन आबंटित किया था और इस धन को कभी भी व्ययगत नहीं किए जाने का निर्देश दिया था।

उन्होंने यह भी याद दिलाया कि एनडीए के शासनकाल में पूर्वोत्तर के विकास के लिए अलग से एक विशेष मंत्रालय बनाया गया था। उन्होंने नेताओं से कहा कि वे भाजपा प्रति भारतीय लोगों के सहज समर्थन का लाभ लें जो 1977 से आज तक किसी राजनैतिक पार्टी को नहीं मिला है। ■

मेहनत की रोटी खायेंगे घर-घर कमल खिलायेंगे : वसुन्धरा राजे

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती वसुन्धरा राजे ने राहुल गांधी के भाषण का करारा जवाब देते हुए कहा कि राहुल कुछ भी कहें राजस्थान की स्वाभिमानी जनता ने तो अब तय कर लिया है कि ''मेहनत की रोटी खायेंगे, घर-घर कमल खिलायेंगे, भाजपा को लायेंगे, खुशहाल राजस्थान बनायेंगे।''

श्रीमती राजे 12 सितम्बर को नागौर जिले के कठौती गांव में लोक देवता बाबा रामदेव के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग अपने बलबूते पर खुद कमाते हैं और अपना पेट भरते हैं। जिन्हें किसी की रोटी के टुकड़े की जरूरत नहीं है। राजस्थान के लोग मेहनत और स्वाभिमान से काम करते है, पसीना बहाते है और उसी पसीने और मेहनत की खाते हैं। मनरेगा में 100 दिन काम की बात करने वाले राहुल ये तो पता कर लेते कि राजस्थान में कई जगह मनरेगा मजदूरों को मजदूरी के रूप में एक रुपया रोज भी मिलता है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा कि गरीबों को बोझ विपक्ष नहीं राहुल और उनकी पार्टी समझती है, जो गरीबों को अपनी ताकत बताती है और अपनी इस ताकत को बढ़ाने के लिए वह गरीब को गरीब ही रखना चाहती है। जबकि हम चाहते है कि हमारे राजस्थान परिवार का एक भी व्यक्ति गरीब न रहे। हम गरीबी खत्म कर पूरे प्रदेश को विकसित करना चाहते हैं और कांग्रेस गरीबी कायम रख प्रदेश का नहीं खुद का विकास चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि 10 गरीब है तो वे 100 हो जाये और 100 गरीब है तो वे 1000 हो जाये और वह गरीबों की ताकत पर राजनीति करती रहे। कैसे लोग है ये? जो ऐसा करने के बाद भी कहते है हम सरकार चलायेंगे। ये कैसे हमारे परिवार को आगे बढ़ायेंगे? ये न देश के गौरव को आगे बढ़ायेंगे और न देश के इतिहास को। ये कहते हैं हम गरीबों को फ्री दवा दे रहे हैं। मैं तो जहां भी गई किसी ने भी मुफ्त इलाज का दावा नहीं किया। सब जगह फ्री दवा की शिकायतें मिली। ये तो फ्री दवा के नाम पर लोगों को जहर दे रहे हैं।

शासक वो है जो सेवा करे

श्रीमती राजे ने कहा कि बाबा रामदेव शासक थे, जिन्होंने राजा बनकर नहीं जनसेवक बनकर लोगों की सेवा की। छुआछूत मिटाने का प्रयास किया। सर्व धर्म समभाव के हामी रहे। इसीलिये वे पीर भी कहलाये। इसलिये सबको बाबा रामदेव से नसीहत लेनी चाहिए।

राक्षसों का अंत हो

श्रीमती राजे ने कहा कि जिस तरह से बाबा रामदेव ने लोगों को भैरव राक्षस से मुक्ति दिलाई उस तरह प्रदेश को महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार, बेरोजगारी जैसे राक्षसों से मुक्ति दिलाने की आवश्यकता है, जो भाजपा ही दिला सकती है।

प्रदेश एक होगा, तो बनेगा नया राजस्थान

श्रीमती राजे ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरा राजस्थान एक होकर कांग्रेस कुशासन से मुक्ति पायेगा, तब जाकर नया राजस्थान बनेगा।

राजस्थान में महिला अस्तित्व खतरे में

श्रीमती राजे ने कहा कि राजस्थान में माता बहने सुरक्षित नहीं है। बढ़ते महिला अत्याचार में प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर आ पहुंचा है। प्रतापगढ़ का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि नवजात बेटियां पैदा होने के साथ ही जमीन में गाड़ दी जाती हैं।

जिस राजस्थान की वजह से हिन्दुस्तान पहचाना जाता था, आज उस राजस्थान पर कलंक का टीका लग रहा है। ■